

माजपा की रिठु तावड़े बीएमसी महापौर पद की उम्मीदवार...

शिंदे गट ने संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर के लिए चुना, चुनाव 11 फरवरी को

मुंबई, 07 फरवरी 2026। मुंबई में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रिठु तावड़े को मेयर का उम्मीदवार बनाया है, जबकि शिवसेना ने संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बाद अब चुनाव अधिकारी के पास मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का पर्चा दाखिल किया जाएगा। इसके बाद 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे मेयर का चुनाव होगा। संभावना है कि शिवसेना उम्मीदवारों को मेयर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा। बीजेपी नेता अमित साठम ने रिठु तावड़े का नाम घोषित किया। तावड़े वार्ड 132 की कांस्टेबल हैं। वहीं घाड़ी वार्ड 5 से चुने गए थे। शिवसेना 15 महीने पर बदलेगी डिप्टी मेयर : शिवसेना के सचिव संजय मोरे ने कहा कि घाड़ी अगले 15 महीने तक डिप्टी मेयर के रूप में काम करेंगे। घाड़ी पहले शिवसेना के वरिष्ठ कांस्टेबल थे। बाद में उन्होंने एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना जॉइन की। शिवसेना ने डिप्टी मेयर का पद चार हिस्सों में बांटकर चार अलग-अलग पार्षदों को मौका देने का फैसला किया है। यह कदम पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने और वरिष्ठ नेताओं को मौका देने के लिए लिया गया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 227 सदस्यीय बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है।



अमेरिका ने पीओके और अक्साई चीन को बताया भारत का हिस्सा

नई दिल्ली, 07 फरवरी 2026। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा के तत्काल बाद संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालय द्वारा जारी नक्शों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन समेत पूरे जम्मू-कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। यूएसटीआर कार्यालय के एक्स पोस्ट पर शेरार किए गए इस नए नक्शों में न केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के सभी हिस्सों को भी भारत की क्षेत्रीय सीमा के भीतर दर्शाया गया है। इससे पहले भारत कई बार अमेरिकी और अन्य वैश्विक एजेंसियों द्वारा जारी नक्शों में जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को गलत प्रस्तुति पर आपत्ति जताता रहा है। अब ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी नक्शा को उन आपत्तियों के बाद सही से तैयार किया गया है। यह कदम भारत के रुख के अनुरूप और अमेरिका की पुरानी नीति से अलग है, क्योंकि पहले अमेरिकी एजेंसियों द्वारा जारी नक्शों में पीओके को विवादित क्षेत्र बताने के लिए डॉटड लाइनों या अलग लेबल का इस्तेमाल किया जाता था। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने 2020 में एक राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के कुछ हिस्सों और गुजरात के जुनागढ़ एवं सर क्रोक पर दावा किया था।



बसपा को कमजोर करने की हो रही साजिश : मायावती

लखनऊ, 07 फरवरी 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर बसपा को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार साजिश की जा रही है। मायावती ने आरोप लगाया कि आज धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, जबकि जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों को जानबूझकर दरकिनारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मायावती ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। लखनऊ में आयोजित इस बैठक में उन्होंने संगठन को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि बसपा कार्यकर्ता विरोधी दलों के साम, दाम, दंड और भेद जैसे हथकंडों के साथ-साथ कुछ स्वार्थी दलित संगठनों के चिन्तन षडयंत्रों का डटकर मुकदमा करते हुए पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखकर संगठन में जरूरी फेरबदल किए जाने हैं।

मलेशिया पहुंचे मोदी को रिसीव करने खुद पहुंचे पीएम इब्राहिम...

पीएम मोदी बोले... ये उनका भारतीयों के लिए प्रेम, यहां जल्द यूपीआई लॉन्च करेंगे

कुआलालंपुर, 07 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 8 साल बाद दो दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे। उन्हें मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर अपनी कार से रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद एयरपोर्ट पर मेवा स्वागत करने आए। वे मुझे अपनी कार से यहां लाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपनी सीट पर भी बैठाया। उन्होंने कहा, यह खास सम्मान भारत और भारतीय समुदाय के प्रति उनके प्यार और सम्मान को दिखाता है। भारत जल्द यहां अपना पॉस्ट सिस्टम यूपीआई लॉन्च करेगा। मोदी ने कहा- पिछले साल मैं आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया नहीं आ सका था, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं जल्द मलेशिया आऊंगा। आज मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। साल 2026 में यह मेरी पहली विदेश यात्रा है।



पीएम मोदी बोले... भारतीयों ने रोटी बनाई को मलाबार परेश से जोड़ा

पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से कहा कि आपने रोटी बनाई को मलाबार परेश से जोड़ा है। नारियल, मसाले और चाय भी हमारे रिश्ते को जोड़ते हैं। चाहे कुआलालंपुर हो या कोच्चि, स्वाद एक जैसे लगते हैं। हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, शाब्दिक इस्लाम क्योंकि हमारी भाषाओं और मूल भाषा में कई शब्द समान हैं। मोदी ने कहा, मैंने सुना है कि मलेशिया में भारतीय संगीत और फिल्मों कापी लोकप्रिय हैं। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन भारत में बहुत से लोगों को यह बात पहले नहीं पता थी। उनके पिछले भारत दौरे के दौरान जब उन्होंने एक पुराना हिंदी गीत गाया, तो उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। भारतीय पीएम ने कहा कि यह जानकर खुशी होती है कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को महान अभिनेता और नेता एमजीआर के तमिल गीत बहुत पसंद हैं।

मोदी ने इंडियन कल्चरल सेंटर का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा

पीएम मोदी ने मलेशिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा। उन्होंने ऐलान किया कि कुआलालंपुर में मौजूद इंडियन कल्चरल सेंटर को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर कहा जाएगा। मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार मानती थी, लेकिन अब भारत निवेश और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। आज भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाता है। चाहे ब्रिटेन हो, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ या अमेरिका, कई देशों ने भारत के साथ व्यापार समझौते किए हैं। भारत आपके दिलों में एक खास जगह रखता है। 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। उस समय आप सभी (भारतीय समुदाय) ने मिलकर भारत की मदद की थी। इसके लिए सभी को धन्यवाद। भारत को आजाद कराने के लिए आपके पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए थे। उनमें से कई के भारत में रिश्तेदार और पड़ोसी थे, फिर भी वे सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होने वालीं थीं।

मलेशियाई पीएम बोले- हमारे भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते

मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है और वे आभारी हैं कि भारत से उनके एक अच्छे दोस्त मलेशिया आए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारत और मलेशिया के बीच आने-जाते वाले पुराने समुद्री उत्सव पुनर्नाम और मजबूत रिश्ते को दिखाता है। उन्होंने कहा कि दूतावास और व्यापार समझौते बनने से पहले ही भारत और मलेशिया के बीच समुद्र के रास्ते संपर्क था। उस समय व्यापारी, विद्वान और नाविक भारत और मलेशिया के बीच आते-जाते थे। उन्होंने भारत में मनाए जाने वाले पुराने समुद्री उत्सव बालीयात्रा का भी जिक्र किया।

मथुरा में एक्सप्रेस-वे पर 6 की मौत, कटेनर ने रौंदा

बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे, चेहरे कुचले, स्वेटर से पहचान

मथुरा, 07 फरवरी 2026। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस से उतरकर खड़े यात्रियों को तेज जकार कटेनर ने रौंदा दिया। हदसे में 6 की मौत पर मौत हो गई। एक गंभीर घायल है। घटना शनिवार तड़के 2.45 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, बस दिल्ली के नागलौंड से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। रास्ते में कुछ यात्रियों ने ड्राइवर को बाथरूम के लिए बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने ग्रीन जॉन की बजाय रास्ते में बस रोक दी। कुछ यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए, तभी पीछे से आ रहे कटेनर ने पहले बस को टक्कर मारी। फिर यात्रियों को रौंदा दिया। कटेनर का चालक मौके से फरार हो गया। हदसे के बाद चीख-पुकार मच गई। हॉर्न पर लाशें बिछ गईं। कुछ यात्रियों के



चेहरे बुरी तरह कुचल गए। इससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। हिममत रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। हदसा सुरीर थाना क्षेत्र में माइल स्टोन-88 के पास हुआ। मृतक संतोष के बेटे अभिनय ने बताया कि रात 10 बजे पापा से बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि वह लोग बस में बैठे

मृतक अनुराग का चेहरा बुरी तरह से कुचला, भाई बाला-स्वेटर से पहचान की

मृतक अनुराग के भाई अनिल गुप्ता ने बताया- मेरे नंबर पर सुबह करीब 7 बजे पुलिस की कॉल आई थी। फोन करने वाले शख्स ने बताया- यमुना एक्सप्रेसवे पर हदसा हो गया है। जिसमें अनुराग की मौत हो चुकी है। उसकी लाश पोस्टमार्टम हाउस पर है। सूचना मिलते ही परिजन को लेकर मैं पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा।

भारत-अमेरिका के साथ ट्रेड डील अर्थव्यवस्था पर डालेगा गंभीर असर : कांग्रेस

नई दिल्ली, 07 फरवरी 2026। कांग्रेस ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को देश के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा है कि यह भारत को अमेरिका का 'डॉग ट्राइंग' बना देगा और किसानों व अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डालेगा। पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख एन खेड़ा ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार अधिरोध (ट्रेड सररलस) वाला साझेदार रहा है। दरकों तक भारत ने अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। लेकिन ट्रंप



प्रशासन की इस डील से भारत को अगले पांच साल में 500 बिलियन डॉलर का आयात करना

होगा यानी आयात तीन गुना बढ़ना पड़ेगा। इससे भारत की आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचेगा। भारत आखिर अमेरिका से क्या खरीदेगा, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि भारत अमेरिका से क्या नहीं लेगा लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या-क्या आयात होगा। इस डील से किसानों की कमर टूटेगी और अमेरिकी किसानों को भारत का बड़ा बाजार मिल जाएगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस समझौते में भारत को रियायत नहीं बल्कि नुकसान मिला है।

भारतीय तटरक्षक बल ने अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, तीन विदेशी जहाज जब्त

नई दिल्ली, 07 फरवरी 2026। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने सुनिश्चित समुद्री हवाई समन्वित अभियान के जरिए अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान से संघर्षप्रस्त क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में तेल और तेल-आधारित कार्गो के अवैध हस्तांतरण में शामिल नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। आईसीजी ने तीन विदेशी जहाजों को जब्त कर लिया है, जिन्हें आगे की जांच के लिए मुंबई बंदरगाह पर लाया जा रहा है। आईसीजी के कमांडर अमित उनियाल ने बताया कि 5 फरवरी को मुंबई से लगभग 100 समुद्री मील पश्चिम में भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों ने तीन सड़िगु जहाजों को रोका। आईसीजी की विशेषज्ञ बॉटिंग टीमों ने जहाजों की लगातार तलाशी ली और जहाज पर बरामद इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पुष्टि की। दस्तावेज का सत्यापन करते चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ की गई। घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने के बाद आपराधिक कार्यप्रणाली की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि तस्करी करने वाले गिरोह ने एक ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई, जिसमें सस्ते तेल को समुद्री जहाजों से ले जाकर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मोटर टैंकरों में स्थानांतरित किया जाता था।

संघ किसी व्यक्ति या विचारधारा के विरुद्ध नहीं वह राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा : भागवत

मुंबई, 07 फरवरी 2026। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत ने शनिवार को मुंबई में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा के विरुद्ध नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहा है। संघ प्रमुख डॉ. भागवत आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित 'नए ध्येय' कार्यक्रम में बोल रहे थे। संघ प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संघ किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा के विरुद्ध नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संघ ने तो अर्धसैकड़ संगठन हैं और न ही सत्ता, प्रतिष्ठा या लोकप्रियता की आकांक्षा रखता है। संघ प्रमुख डॉ. भागवत ने कहा कि संघ का कार्य अपने आप में अद्वितीय है, जिसे समझने के लिए न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं।

विकसित भारत की ओर बड़ी छलांग, अमेरिका ने खोले दरवाजे....

30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में सीधी एंट्री : गोयल

नई दिल्ली, 07 फरवरी 2026। भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर (करीब 45,29,069.80 रुपये) के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय है, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पैठ बढ़ाने का एक बड़ा मौका भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अमेरिका के साथ हुई इस डील पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने की दिशा में यह समझौता अहम साबित होगा। गोयल ने कहा कि हमारे निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मोस्ट प्रॉफिट ड्यूटी के साथ खुलती है। कल देर रात जो भारत-अमेरिका के बीच संयुक्त बयान तय हुआ, दुनिया के सामने रखा गया, इसका हर तरफ स्वागत हुआ है। गोयल ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। यह दिन विकसित भारत के लिए अहम माना जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि आज का दिन विकसित भारत 2047 की राह में एक महत्वपूर्ण दिन है, और उन्होंने अंतरिम व्यापार समझौते को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता फरवरी 2025 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य प्रति



दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही बातचीत

उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए एक भव्य, दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की प्रशंसा की। द्विपक्षीय समझौते की वार्ता करते हुए गोयल ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित रही है। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। गोयल ने इस दिन को भारत-अमेरिका व्यापार इतिहास में 'सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन' बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा से अवगत कराते हुए इसे भारत के आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने निर्यातकों, लघु व मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए संभावित लाभों पर प्रकाश डालते हुए, गोयल ने समझौते को भारत की विकसित भारत 2047 की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, जिसमें रोजगार सृजन, मजबूत व्यापार संबंध और नवाचार और निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया।

वर्ष 500 अरब डॉलर का निर्यात कारोबार हासिल करना था। गोयल ने समझौते की घोषणा के बाद देशभर में फैली खुशी और आशावाद की भावना पर प्रकाश डाला।

रत्न और फार्मा कंपनियों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा... कि नए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत, कई प्रमुख वस्तुओं के अमेरिका को निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। रत्न और आभूषणों के साथ-साथ औषधीय उत्पादों को भी अब शुल्क-मुक्त निर्यात की जाएगी। कृषि क्षेत्र में, कई भारतीय उत्पाद अब बिना किसी शुल्क के संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जा सकेंगे। इनमें चाय, मसाले, नारियल तेल, वनस्पति तेल, सुपारी, जलजल नट्स, शाहबलूत और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां शामिल हैं। पीयूष गोयल के अनुसार, सब्जी की जई, अनाज, जौ, बेकरी उत्पाद, कोको उत्पाद, तिल के बीज, खसखस और खंड फलों के रस पर भी कोई परस्परिक शुल्क नहीं लगेगा।

फार्मा, कॉफी और आम का बिना किसी टैरिफ के हो सकेगा निर्यात

गोयल का कहना है कि रत्न, फार्मा, कॉफी, आम और अन्य कई वस्तुएं अमेरिका को शुल्क-मुक्त निर्यात की जाएगी। कृषि क्षेत्र में, कई भारतीय उत्पाद अब बिना किसी शुल्क के संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जा सकेंगे। इनमें चाय, मसाले, नारियल तेल, वनस्पति तेल, सुपारी, जलजल नट्स, शाहबलूत और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां शामिल हैं। पीयूष गोयल के अनुसार, सब्जी की जई, अनाज, जौ, बेकरी उत्पाद, कोको उत्पाद, तिल के बीज, खसखस और खंड फलों के रस पर भी कोई परस्परिक शुल्क नहीं लगेगा।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति के आकलन के लिए जम्मू में बैठक की



जम्मू, 07 फरवरी 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक लोकभवन में हुई जिसमें जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लू और डीजीपी नलिन प्रभात सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक समाप्त होने के बाद गृह मंत्री शनिवार शाम दिल्ली लौटेंगे। इससे पहले अमित शाह गुरुवार देर रात यहां पहुंचे और शुक्रवार को कटुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गुरनाम और बोबिया स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की अग्रिम चौकियों का दौरा कर

अपने दो दिवसीय क्षेत्रीय दौरे की शुरुआत की। कटुआ से लौटने पर शाह ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें अन्य अधिकारियों के साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उपस्थित थे। बैठक में जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कई पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें नींद की पत्र सौंपे। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को गृह मंत्री से भी मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया, 'मैंने जम्मू में राज्य पदाधिकारियों, जम्मू-कश्मीर भाजपा के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। भाजपा मोदीजी की विकास पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए काम करती रहेगी, साथ ही एक विकसित और सुरक्षित जम्मू-कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए संगठन का विस्तार भी करेगी।

संपादकीय

जवाबदेही के दायरे में आए टैक कंपनियां

यह लेख डिजिटल युग में मुला दिए जाने के अधिकार पर केन्द्रित है, बताया है कि कैसे पुराने डिजिटल पदविह व्यक्तियों के लिए बाधा बन सकते हैं। यह फेक न्यूज़, ऑनलाइन और डीपफेक जैसे डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग पर एकाग्र उल्ला है, और तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही पर जोर देता है। भारत में एक सशक्त कानून की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत निजता और सार्वजनिक हित को संतुलित करे, साथ ही आईई के सकारात्मक उपयोग और मजबूत कानूनी ढांचे की कालगत करता है...

सुबह की पहली किरण के साथ जब हम अपने स्मार्टफोन का स्क्रीन अनलॉक करते हैं, तो हम केवल एक उपकरण नहीं खोलते, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो कभी सोती नहीं है। यह डिजिटल दुनिया जितनी चमकदार है, उतनी ही बेरहम भी। आज हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल मीडिया के गलियारों में बीत रहा है। हमारी पहचान, रिश्ते और समाज में प्रतिष्ठा अब हमारे पदचिह्नों यानी डिजिटल फुटप्रिंट्स से तय होती है, पर समया तब शुरू होती है जब वे पदचिह्न हमारी वर्तमान पहचान के लिए बोझ बन जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की, जिस पर दस साल पहले एक छोटा आरोप लगा था। अदालत ने उसे सम्मान बरी कर दिया, लेकिन आज जब कोई कंपनी उसे नौकरी देने के लिए उसका नाम गुगल करती है, तो सबसे ऊपर वही पुरानी गिरफ्तारी की खबर चमकती है। यही वह बिंदु है जहाँ राइट टू बी फॉरगटन यानी भुला दिए जाने का अधिकार विलासिता नहीं, बल्कि जीने के अधिकार का हिस्सा बन जाता है।

डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग आज एक महामारी की तरह फैल चुका है। फेक न्यूज़, ट्रोलिंग और साइबरबुलिंग ने वचुअल स्पेस को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। सबसे भयावह रूप तब सामने आता है, जब किसी की निजी जानकारी या तस्वीरें उसकी मर्जी के बिना सार्वजनिक कर दी जाती हैं। इसे डॉक्सिंग कहा जाता है। यह केवल तकनीक का गलत इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह एक इंसान की गरिमा पर सीधा हमला है। जब कोई अपमानजनक सामग्री एक बार वायरल हो जाती है, तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव हो जाता है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से मरता नहीं है, वह बस दबा रहता है और समय-समय पर बाहर आता रहता है।

यहाँ पर राइट टू बी फॉरगटन की अवधारणा उम्मीद की किरण है। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने पुराने, अप्रासंगिक या गलत डिजिटल रिकॉर्ड्स को हटवा सके। यूरोपीय संघ का एक कानून इस मामले में एक मिसाल है। वहाँ के एक चर्चित मामले में यह तय हुआ कि अगर कोई जानकारी अब जरूरी नहीं है, तो उसे सर्व रिकल्ट्स से हटाना होगा। भारत में भी इस अधिकार की सुगव्याहृत तेज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुद्दुच्चामी केस में निजता को मौलिक अधिकार तो माना, लेकिन राइट टू बी फॉरगटन अभी भी एक कानूनी धुंध में फंसा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में माना कि एक व्यक्ति को अपनी पुरानी गलतियाँ या तस्वीरें से आगे बने न का हक है। क्या हमारे पास इसके लिए कोई ठोस कानून है?

भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 इस दिशा में एक कदम जरूर है। यह डाटा मिटाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। जब कोई व्यक्ति अपना डाटा हटवाने की मांग करता है, तो उसके सामने अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत पारदर्शिता की दीवार खड़ी हो जाती है।

बीस साल बाद फिर मायावती का दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ फार्मूला



अनंद कुमार, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी करीब 15 सालों से सत्ता से बाहर है। 2007 से 2012 तक सत्ता में रही बसपा को पिछले तीन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान तीन लोकसभा चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में यह धारणा आम तौर पर बनने लगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का कालखंड खत्म हो चुका है। ऐसा इस लिये भी कहा जा रहा था क्योंकि मायावती ने चुनाव प्रचार से भी काफी हद तक किनारा कर लिया था। वास्तव में अंततः 2007 में विधानसभा चुनाव जीती बसपा की उस समय की चुनावी रणनीति की जोयें तो 2007 का चुनाव मायावती को सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से जीती थी। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने राजनीतिक इतिहास रच दिया। 2007 में मायावती ने सामाजिक समीकरण साधकर 403 सीटों में से 206 सीटों पर कब्जा जमाया और कुल 30.43 प्रतिशत वोट हासिल किए। बसपा सुप्रीमो की यह जीत दलितों के परंपरागत वोट बैंक के अलावा ब्राह्मणों और कुछ गैर-यादव पिछड़ी जातियों

तथा मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से संभव हुई थी। यह और बात है कि इसके बाद मायावती का यह फार्मूला दोबारा परवाना नहीं चढ़ पाया।

बहरहाल, अबकी करीब 20 सालों के बाद एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिये बसपा के पक्ष में दलितों के साथ ब्राह्मणों एवं मुसलमानों के वोटों की गोलबंदी देखी जा रही है। ब्राह्मणों और मुसलमानों के एक बार फिर बसपा की तरफ रुख करने की वजह में जाया जाए तो ऐसा लगता है कि योगी राज में ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनके साथ यह सरकार नाइसपही कर रही है। नौकरशाही से लेकर सरकार तक में महत्वपूर्ण पदों से ब्राह्मणों को दूर रखा गया है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में ब्राह्मण नेताओं का प्रवेश अधिक देखा गया है। जनवरी 2026 में अंबेडकर नगर से भाजपा के दिग्गज नेता राधेश्याम पांडे 51-100 ब्राह्मण समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हुए। उन्होंने मायावती से मुलाकात कर पार्टी जॉईन की। दिसंबर 2025 में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता जैसे जितेंद्र मिश्रा, दीपक द्विवेदी, नीरज पांडे, विशाल मिश्रा, वैभव दुबे, अनुराग शुक्ला, मोहित शर्मा भाजपा से बसपा में शामिल हुए। यह 2027 चुनाव से पहले भाजपा को झटका था। जनवरी 2026 में एक अन्य बड़े जीत मुख्यतः निचली जातियों के वोटों से आई। ठाकुरों और अन्य ऊपरी जातियों ने भी सोमिंत लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पिछड़ी जातियों ने भी बसपा की ओर रुख किया। गैर-यादव और गैर-ऊपरी अन्य पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत मतदाताओं ने पार्टी चुनी। कुल पिछड़े वर्ग के कई खंडों से वोट उभरे, जिसने सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाया। बसपा ने 110 पिछड़े वर्ग के



उम्मीदवार मैदान में उतारे।

इसकी सबसे बड़ी मिसाल बताते हैं। बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की भी मौत के लिये मुस्लिम समाज कहीं न कहीं अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगाता है कि विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अतीक और मुख्तार को लेकर उकसाया नहीं होता तो आज वह जिंदा होते। दलित वोटों ने बसपा को पूर्ण समर्थन दिया। जाटव समुदाय के 86 प्रतिशत मतदाताओं ने मायावती को चुना, जबकि वाल्मीकि जाति के 71 प्रतिशत ने पार्टी को तरजीह दी। पासी समुदाय से 53 प्रतिशत और अन्य अनुसूचित जातियों से 58 प्रतिशत वोट बसपा के खाते में आए। इन दलित उपाजातियों की मजबूत पकड़ ने पार्टी को आमार्ण प्रदान किया, क्योंकि दलित उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 21 प्रतिशत हैं। ऊपरी जातियों में ब्राह्मणों का 16 प्रतिशत समर्थन मिला, जो निर्णायक साबित हुआ। बसपा ने 51 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 20 जीते, लेकिन यह जीत मुख्यतः निचली जातियों के वोटों से आई। ठाकुरों और अन्य ऊपरी जातियों ने भी सोमिंत लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पिछड़ी जातियों ने भी बसपा की ओर रुख किया। गैर-यादव और गैर-ऊपरी अन्य पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत मतदाताओं ने पार्टी चुनी। कुल पिछड़े वर्ग के कई खंडों से वोट उभरे, जिसने सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाया। बसपा ने 110 पिछड़े वर्ग के

उम्मीदवार मैदान में उतारे। यह समर्थन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से छिटके वोटों का परिणाम था, जो विकास और सुरासन के वादों से प्रभावित हुए। मुस्लिम मतदाताओं का योगदान सबसे चमत्कारिक रहा। 2007 में बसपा को कुल वोटों में मुस्लिम वोट 10 प्रतिशत से अधिक थे। एक सर्वे के अनुसार 17 प्रतिशत मुस्लिमों ने पार्टी को समर्थन दिया। पार्टी ने 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 29 विधायक बने। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19 प्रतिशत होने के बावजूद यह समर्थन बहुमत के लिए जरूरी साबित हुआ। समाजवादी पार्टी से नाराज मुस्लिमों ने बसपा को मौका दिया, क्योंकि मायावती ने अल्पसंख्यक कल्याण के वादे किए।

मायावती की रणनीति ने जातिगत बंधनों को तोड़ दिया। ब्राह्मण गठजोड़ की बात भले ही प्रचारित हुई, लेकिन वास्तव में जाटव, वाल्मीकि, पासी जैसे दलितों के साथ अन्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत, ब्राह्मणों के 16 प्रतिशत और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत वोटों ने चमत्कार रचा। बसपा का वोट प्रतिशत 2002 के 23 से बढ़कर 30 हो गया। पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों से ऊपरी जातियों को लुभाया, जबकि मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। यह जीत सामाजिक न्याय की मिसाल बनी। मायावती ने सत्ता में आकर अपराध पर अंकुश लगाया और विकास कार्य तेज किए। लेकिन जातिगत समीकरण की बारीकी ने राजनीति को नया आयाम दिया। दलितों का वोट 80-86 प्रतिशत तक रहा, ऊपरी जातियों से 16-20 उम्मीदवार जीते, पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत समर्थन और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत ने पूर्ण बहुमत सुनिश्चित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरह से पंडित कांड खेल रही है, इसका ताजा

उदाहरण यह बताता है कि उनका ब्राह्मणों के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को लेकर सर्वप्रथम विशेषकर ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद से चल रही राजनीति पर और इसके बाद बॉलीवुड फिल्म 'घूसखोर पंडित' के खिलाफ ब्राह्मणों के पक्ष में बयान देने में देरी नहीं की। इससे पहले यूजीसी के नये नियम पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा था कि इस नये कानून से किसी को बिना वजह प्रताड़ित नहीं किया जाये। देश भर में 'घूसखोर पंडित' फिल्म के विरोध के बीच बसपा की राष्ट्रीय अय्यक मायावती ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर ब्राह्मण कांड खेल दिया है। वहीं यूजीसी प्रकरण में असहज हुई भाजपा भी अब फिल्म के मुद्दे पर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म पर एक आईआईए के निदेश देकर इस वर्ग के साथ का संदेश दिया।

बसपा प्रमुख ने इस मामले में शुक्रवार 06 फरवरी को एक्स पर लिखा, 'यह बड़े दुःख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी 'पंडित' को घुसपैठिया अय्यक पूरे देश में जो इन्का अपमान व आनाद किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस जातिव्युत्क फिल्म पर केंद्र तेज किए। लेकिन जातिगत समीकरण की बारीकी ने राजनीति को नया आयाम दिया। दलितों का वोट 80-86 प्रतिशत तक रहा, ऊपरी जातियों से 16-20 उम्मीदवार जीते, पिछड़े वर्ग के 30 प्रतिशत समर्थन और मुस्लिमों के 17 प्रतिशत ने पूर्ण बहुमत सुनिश्चित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरह से पंडित कांड खेल रही है, इसका ताजा

गड़ों वाली व्यवस्था और खतरे में पड़ता जीवन



ललित गर्ग, पटना, बिहार

गड़ों में गिरी व्यवस्था में समाप्त होता जीवन आज के भारत की एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर मन भीतर तक सिहर उठता है। नोएडा में कार सवार युवा इंजीनियर की गड़ों में गिरकर मौत का दर्द अभी समाज के मन से उतरा भी नहीं था कि दिल्ली में बाइक सवार युवक की जान एक खुले गड़ों ने ली ली। दोनों घटनाओं में समाजता यह है कि गड़ों प्रशासन द्वारा विकास या मरम्मत के नाम पर खोदे गए थे और दोनों जगह न तो कोई बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न रोशनी की व्यवस्था। मानो व्यवस्था ने पहले गड़ों खोदा और फिर निश्चित होकर वहाँ से हट गई कि अब जो होगा, वह नागरिक की किस्मत है। यही वह सोच है जो किसी भी समाज को भीतर से खोखला कर देती है। प्रश्न यह नहीं है कि गड़ों क्यों खोदे

गए, प्रश्न यह है कि गड़ों खोदकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया। क्या विकास का अर्थ यह हो गया है कि सड़कों पर चरते हुए हर नागरिक अपनी जान हथेली पर रखे। क्या शहरों की चमक-दमक और बड़े-बड़े दावों के बीच आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। यह सामान्य हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब भीतें सामान्य लगने लगीं, तब व्यवस्था की संवेदनशीलता मर चुकी होती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड़ों या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निर्लिखित कर दिए जाते हैं, जांच समितियाँ बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है। सवाल यह है कि क्या निलंबन से मरे हुए बेटे लौट आते हैं, क्या जांच समितियों से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जब तक जवाबदेही केवल कागजों पर सिमटी रहेगी, तब तक गड़ों में गिरती जिंदगियाँ यूँ ही व्यवस्था का शिकार बनती रहेंगी। इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएँ कम से कम चर्चा में तो



आती हैं, मीडिया सवाल तो उठता है, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों में कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। यह सामान्य हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब भीतें सामान्य लगने लगीं, तब व्यवस्था की संवेदनशीलता मर चुकी होती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड़ों या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निर्लिखित कर दिए जाते हैं, जांच समितियाँ बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है। सवाल यह है कि क्या निलंबन से मरे हुए बेटे लौट आते हैं, क्या जांच समितियों से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जब तक जवाबदेही केवल कागजों पर सिमटी रहेगी, तब तक गड़ों में गिरती जिंदगियाँ यूँ ही व्यवस्था का शिकार बनती रहेंगी। इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएँ कम से कम चर्चा में तो

की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें नागरिक को एक आंकड़ा समझ लिया गया है। फाइलों में वह एक केस नंबर है, सड़क पर वह एक बाधा और हादसे के नाद वह एक आंकड़ा। जब तक प्रशासन और शासन की दृष्टि में नागरिक का जीवन सर्वोपरि मूल्य नहीं बनेगा, तब तक हर नया गड़ एक नई मौत की संभावना बनकर खड़ा रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या इन गड़ों के लिए कभी उच्च स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी तय होगी। क्या कभी ऐसा होगा कि किसी बे पद पर बैठे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके विभाग की लापरवाही से एक जान गई, इसलिए आप पद पर बने रहने के नैतिक अधिकारी नहीं हैं। भ्रष्ट शासन के समाप्त होने की बड़ी-बड़ी घोषणाएँ हर चुनाव में सुनाई देती हैं। पोस्टर बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जमीन पर गड़ों वैसे ही रहते हैं। यदि भ्रष्टाचार केवल रिश्तत लेने तक सीमित होता तो शायद उसे पहचानना आसान होता, लेकिन यह जो संवेदनहीन भ्रष्टाचार है, जहाँ नियमों की संवेदना नहीं जुड़ी, तो वह रफ्तार विनाश की ओर ही ले जाएगी। यह विडंबना ही है कि हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, लेकिन स्मार्ट बैरिकेडिंग, स्मार्ट चेतावनी और स्मार्ट जिम्मेदारी पर बात करना भूल जाते हैं। तकनीक के युग में भी एक साधारण चेतावनी बोर्ड लगाना हमारे तंत्र को याद नहीं रहता। दरअसल समस्या केवल लापरवाही

की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें नागरिक को एक आंकड़ा समझ लिया गया है। फाइलों में वह एक केस नंबर है, सड़क पर वह एक बाधा और हादसे के नाद वह एक आंकड़ा। जब तक प्रशासन और शासन की दृष्टि में नागरिक का जीवन सर्वोपरि मूल्य नहीं बनेगा, तब तक हर नया गड़ एक नई मौत की संभावना बनकर खड़ा रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या इन गड़ों के लिए कभी उच्च स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी तय होगी। क्या कभी ऐसा होगा कि किसी बे पद पर बैठे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके विभाग की लापरवाही से एक जान गई, इसलिए आप पद पर बने रहने के नैतिक अधिकारी नहीं हैं। भ्रष्ट शासन के समाप्त होने की बड़ी-बड़ी घोषणाएँ हर चुनाव में सुनाई देती हैं। पोस्टर बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जमीन पर गड़ों वैसे ही रहते हैं। यदि भ्रष्टाचार केवल रिश्तत लेने तक सीमित होता तो शायद उसे पहचानना आसान होता, लेकिन यह जो संवेदनहीन भ्रष्टाचार है, जहाँ नियमों की संवेदना नहीं जुड़ी, तो वह रफ्तार विनाश की ओर ही ले जाएगी। यह विडंबना ही है कि हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, लेकिन स्मार्ट बैरिकेडिंग, स्मार्ट चेतावनी और स्मार्ट जिम्मेदारी पर बात करना भूल जाते हैं। तकनीक के युग में भी एक साधारण चेतावनी बोर्ड लगाना हमारे तंत्र को याद नहीं रहता। दरअसल समस्या केवल लापरवाही

पितृ-दोष बनाम प्रो-मैक्स-दोष

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उदरुथ

शिवपालगंज के इतिहास में ऐसा खलबली का दौर कभी नहीं आया था, जब स्थानीय जेनजी पंडितों ने डिजिटल पितृदोष की खोज की। मुद्दा यह नहीं था कि गंज के युवा बेरोजगार हैं, बल्कि मुद्दा यह था कि उन्होंने सामूहिक रूप से यह मान लिया कि उनके पूर्वजों की आत्माएँ स्वर्ग में केवल इसलिए दुःखी हैं क्योंकि उनके पोते-पोतियों ने उनकी पुरानी तस्वीरों को इस्ट्रामा फिल्टर लगाकर काला-गोरा कर दिया है। वैद्य जी ने चर्या नाम पर टिकाते हुए कहा, बेटा, यह पितृ पद नहीं, यह तो प्रोमैक्स पद चल रहा है। गंज का युवा अब श्राद्ध में कौनों को खीर नहीं खिला रहा था, बल्कि कौनों के साथ सेल्फी लेकर उसे नेचर वाइब्स के कैप्शन के साथ पोस्ट कर रहा था। शहर से लौटे एक स्वयंभू दार्शनिक ने यह अफवाह फैला दी कि अगर आपके दादाजी की आत्मा को शांति चाहिए, तो आपको उनकी पसंदीदा चीज का डिजिटल त्याग करना होगा। अब गंज की गलियों में एक अजीब सा सनाटा पसर गया। बड़ी पहलवान का बेटा, जो दिन भर रील देखाता था, अब हाथ में स्मार्टफोन लिए ऐसे कांप रहा था जैसे उसने कोई भार पकड़ लिया हो। समस्या यह थी कि उसे अपने दादाजी की आत्मा के लिए नेटफिलक्स का पासवर्ड छोड़ना था। व्यंग्य की धार देखिए, जिस पीढ़ी ने अपने माता-पिता की बात कभी नहीं मानी, वह अब एक अदृश्य रूढ़ के नाम पर अपना डेटा पैक कुर्बान करने को तैयार बैठे थी। गंज के नुकड़ पर बहस छिड़ गई कि क्या पूर्वजों को क्लाउड स्टोरेज में जगह मिलती है? खन्ना मास्टर ने तर्क दिया कि अगर आत्मा अजर-अमर है, तो उसे 5जी की गति से मोक्ष मिलना चाहिए। इसी बीच, एक नौजवान ने घोषणा कर दी कि उसे सपने में उसके परदादा आए थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी फोटो पर एक लाख लाइक्स नहीं आएंगे, वे वैकुंठ के वाई-फाई का एक्सेस नहीं पाएंगे। इस आध्यात्मिक स्कैम ने गंज को दो गुटों में बाँट दिया—एक वो पूजा-पाठ में विश्वास रखते थे, और दूसरे वो जो एंगोरीटिम को ही नया देवता मान चुके थे। जेनजी की इस नई भक्ति ने गंज के मंदिरों का स्वरूप ही बदल दिया। अब वहाँ घंटी बजने के बजाय नोटिफिकेशन टोन सुनाई देती थी। लड़के अपनी मजदूरी दीवार पर लिखने के बजाय मंदिर के चेक-इन पर फीलिंग ब्लेसड विथ 6.9 अमंत्र टैग कर रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि धर्म का ऐसा अपडेटेड वर्जन आएगा जहाँ पापों का प्रार्थना अफालो करके किया जाएगा। वैद्य जी ने चुटकी लीते हुए कहा, यहाँ तो नरक के द्वार पर भी शायद बायोमेट्रिक मशीन लग गई है, वरना ये बालक इतने अंधश्रद्धासित न होते। तभी गंज में एक और संकट खड़ा हुआ—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाम पितृ शक्ति। गंज के एक चालाक लड़के ने अपने स्वर्गवासी बाबा की आवाज को एआई से क्लोन कर लिया और अब वह बाबा की आवाज में पूरे मोहल्ले को घंट टट रहा था। बूढ़े परेशान थे कि जो आदमी मरते वक्त ठीक से बोल नहीं पाता था, वह अब शुद्ध अंग्रेजी में सेल्फ-लव और टॉक्सिक रिलेशनशिप पर ज्ञान कैसे दे रहा है? यह व्यंग्य नहीं, बल्कि गंज की वह विडंबना थी जहाँ तकनीक ने यमराज के रजिस्टर को भी एक्सेल शीट में बदलने की कोशिश की थी। पूरा गंज इस नए डिजिटल मोक्ष के नशे में ऐसा डूबा कि खेतों में फसल की जगह रज के तलाश होने लगीं। लोग गाय का दूध दुहने के बजाय गाय का पीओबी (पाइंट ऑफ व्यू) शूट करने लगे। गंज के कुत्ते भी कम्प्यूज थे कि उन्हें रोटी मिलेगी या सिर्फ उनकी फोटो खींचकर एनिमल लवर का टैग लगाया जाएगा। श्रीलाल शुक्ल के शब्दों में, विकास की गाड़ी गंज की कीचड़ में ऐसी फंसी थी कि टायर जितना घूमता था, कीचड़ उतना ही चेहेरे पर आता था। फर्क बस इतना था कि इस बार कीचड़ एस्थेटिक लग रहा था। इस महा-व्यंग्य का चरमोत्कर्ष तब आया जब गंज के सबसे बड़े डिजिटल बाबा ने ऐलान किया कि कल सूर्योदय के समय वे सीधे स्वर्ग से लाइव प्रसारण करेंगे और सबके पूर्वजों की डिमांड लिस्ट दिखाएंगे। पूरा गंज अपनी छतों पर फोन लेकर खड़ा हो गया। सबकी धड़कनें तेज थीं, क्या वाकई पूर्वजों को आईफोन 17 चाहिए या वे सिर्फ पुरानी धोती से खुश हैं? सर्वसेस इतना था कि गंज की पूरी बिजली कट गई, पर पावर बैंक के सहारे उम्मीद की लौ जलती रही। ठीक उसी समय, जब लाइव प्रसारण शुरू होने वाला था, स्क्रीन पर बाबा का चेहरा नहीं आया। स्क्रीन काली पड़ गई और एक मोटा सा मैसेज फ्लैश हुआ आपका मासिक इंटरनेट कोटा समाप्त हो गया है। सनाटा छा गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब पड़ोस के बंद पड़े पुरतैनी खंडहर से एक जोरदार ठहका सुनाई दिया। लोग भागे-भाग वहाँ पहुंचे तो देखा कि गंज का सबसे पुराना और अनपढ़ चौकीदार, जो सालों से मौन था, हाथ में एक पुराना रॉडियो लिए नाच रहा था।

जोर पकड़ता एक बच्चे का चलन, चीन-जापान जैसा न हो देश का हाल

क्षमा शर्मा
दिल्ली के सर्वे बताते हैं कि अब महिलाएँ 30 की उम्र के बाद संतान चाहती हैं, जिससे 30-35 वर्ष की माताओं की संख्या बढ़ेगी है। शिक्षा, करियर और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के कारण, विवाह और बच्चे देर से हो रहे हैं। महंगे पालन-पोषण के चलते एक बच्चे का चलन भी बढ़ रहा है। लेखिका चीन-जापान के अनुभवों का हवाला देते हुए भारत में भविष्य की जनसांख्यिकीय चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करती हैं, जहाँ युवा आबादी की कमी हो सकती है। पिछले दिनों दिल्ली में महिलाओं पर किए गए एक सर्वे में बताया गया कि अब स्त्रियाँ 30 की उम्र के बाद ही संतान चाहती हैं। 2024 में किए गए एक अन्य सर्वे में पता चला था कि चार में से एक बच्चे को 30 से अधिक उम्र वाली महिला ने जन्म दिया। 30 से 35 वर्ष की माताओं की संख्या 2005 से 2024 तक 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.9

प्रतिशत हो गई। 20 से 24 साल की उम्र में मां बनने वाली महिलाओं की संख्या 2024 में घटकर 27.1 प्रतिशत रह गई। लंबे समय तक माना जाता रहा है कि महिलाओं की मां बनने की उम्र 30 के बाद ठीक नहीं होती, लेकिन अब वक्त बदल गया है। स्त्रियाँ अब पढ़ना चाहती हैं। नौकरी करना चाहती हैं। तरकी के लिए नौकरियाँ बदलती भी रहती हैं। अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी उनका ध्यान बढ़ा है। विवाह उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा। यदि विवाह करती भी हैं, तो देर से। एक जमाने में यदि किसी लड़की की उम्र 30 के पार पहुंच जाती थी, तो मान लिया जाता था कि अब उसका विवाह नहीं होगा या कैसे होगा, क्योंकि इस उम्र तक तो लड़के ही कुंवारे नहीं बेटे रहते, लेकिन अब प्रायः लड़के-लड़कियों के विवाह 30 के बाद की उम्र में हो रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण बढ़ता शहरीकरण भी है। फिर विवाह के बाद वे लोग एकदम से बच्चे नहीं चाहते।



पहले एक नई जीवनशैली में रचना-बसना चाहते हैं, फिर बच्चों के बारे में सोचते हैं। इन दिनों मध्यवर्ग में एक बच्चे का चलन भी बढ़ा है। इसका कारण यह कि इन दिनों बच्चे पालना महंगा है। यदि माता-पिता दोनों भी कमाते हैं, तो बताया जाता है कि एक बच्चे की देखभाल, शिक्षा-दीक्षा में ही एक वेतन खर्च हो जाता है। एक बच्चे के बारे में पुरानी अवधारणा थी कि वह अपने को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे जीवनभर साथीपन की कमी सालती है। अब यह भी नहीं रहता कि बेटे है, तो बेटा जरूर चाहिए। कुछ दिन पहले एक अखबार ने उन माता-पिता से बातचीत की थी, जिनके एक बेटा या एक बेटा था। उन अभिभावकों ने बताया था कि उनके एक बच्चे को कभी कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वे जीवन को जीना जल्दी सीख जाते हैं। अपना काम खुद करते हैं। अधिक अनुशासित होते हैं। अपने देश में उस पीढ़ी को अधिक समय नहीं बीता है, जब घर में पांच-छह भाई-बहन होना मामूली बात थी। घर में आय का साधन एकमात्र कमाने वाले पिता होते थे। सरकारी स्कूलों में

पढ़कर भी बच्चे ठीक-ठाक नौकरी पा जाते थे। उनके विवाह भी 30 से पहले हो जाते थे। उन दिनों नौकरी करने वाली स्त्री का मतलब किसी आपदा की मारी कोई स्त्री ही होती थी। स्त्री की पढ़ाई का मतलब उसकी नौकरी या आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि यह माना जाता था कि अगर कहीं दूर-दूर ब्याह दी जाए, तो कम से कम चिट्ठी-पत्री लिखकर अपना हाल-चाल तो दे सके। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब देश में अल्ट्रासाउंड के जरिये गर्भ में ही लड़कियों को मारने वालों की बाढ़ आ गई। भ्रूण हत्या पर हलाकति सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन अब भी यदा-कदा इसकी खबरें आती रहती हैं, लेकिन जैसे-जैसे लड़कियाँ पढ़ी-लिखीं, आगे बढ़ीं, उन्होंने अपने लिए बनाई गई छवियों को ध्वस्त कर दिया। 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया, तब से अपने यहां स्त्रियों के मसले भी जोर-शोर से उठाए गए। उनकी शिक्षा और

आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया गया। विवाह और बच्चे पहली प्राथमिकता से बहुत पीछे चले गए। आज किसी साधन-संपन्न लड़की से पूछें या किसी गरीब से, सब इस बात पर एकमत हैं कि पहले वे पढ़ना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, उसके बाद ही शादी आदि के बारे में सोचेंगी। अब हम दो-हमारे दो जैसे नारे कहीं सुनाई नहीं देते। स्त्रियों के नजरिये से देखा जाए, तो यह ठीक मालूम पड़ता है कि एक बच्चा हो, लेकिन विश्व स्तर पर जो बातें दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि भारत को भी 50 साल बाद यह ही भ्रूणतना पड़े। एक समय में चीन को जनसंख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा थी। वहाँ की सरकार ने एक बच्चा नीति को सख्ती से लागू किया। अब उसी चीन की हालत क्या है। वहाँ लगातार युवाओं की कमी हो रही है और वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण वहाँ की सरकार युवाओं को तरह-तरह के प्रलोभन दे रही है।

वंशावली अपडेट और मेडिकल सीट सेट ? एहसान अहमद-अरमान अहमद मामले ने सिस्टम की उड़ाई नींद

दस्तावेजों का खेल या नियमों का मेल? आरोपों ने आरक्षण और एडमिशन प्रक्रिया पर खड़े किए तीखे सवाल

- पिता बदला या फाइलें फिसली? एहसान अहमद-अरमान अहमद मामले में जांच की मांग तेज...
- मेडिकल सीट या दस्तावेजों का खेल? शिकायत ने खोल दी सिस्टम की परतें
- कागज जीते या मेरिट हारी? कांकेर मेडिकल एडमिशन पर उठे बड़े सवाल
- रिकॉर्ड में दो पहचान! अभिषेक तिवारी की शिकायत से प्रशासनिक सिस्टम कटघरे में...

आरक्षण की राह या दस्तावेजों की वाह? मेडिकल प्रवेश पर बड़ा विवाद

वंशावली से लेकर एडमिशन तक...फाइलों की कहानी पर व्यंग्यात्मक एक्सपोज

मुहूर्ते तेज, जांच सुस्त? मेडिकल एडमिशन मामले में प्रशासन पर सवाल

नाम बदला या नियम झुके? दस्तावेजों को लेकर उठी जांच की मांग

शिकायत बनी सुर्खी — मेडिकल सीट पर 'कागजी सर्जरी' के आरोप



—सूत्र डेस्क—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ की शांत फाइलों के बीच एक ऐसा मामला सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहा है, जो अगर सच निकला तो यह सिर्फ एक छत्र का नहीं, बल्कि पूरी दस्तावेज व्यवस्था का 'मेडिकल टेस्ट' बन जाएगा, आरोप है कि एक मेडिकल प्रवेश के पीछे कागजों की ऐसी कहानी लिखी गई, जिसमें रिश्ते भी बदल गए और पहचान भी —और सिस्टम शायद आंखें मूंदे बैठा रहा, अब सवाल यह है कि यह सिर्फ संयोग है या फिर 'डॉक्यूमेंट इंजीनियरिंग' की कोई नई तकनीक? बता दें कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल एडमिशन से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी फाइलों की सच्चाई पर व्यंग्य का आईना लगा दिया है, शिकायतकर्ताओं का दावा है कि एहसान अहमद और उनके पुत्र अरमान अहमद से जुड़े दस्तावेजों में ऐसे बदलाव हुए, जिन्हें देखकर आम आदमी यही पूछ रहा है... क्या अब सरकारी रिकॉर्ड भी 'एडिटेड मोड' में चल रहे हैं? यह स्पष्ट है कि आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, वे सिस्टम की सुस्ती और मुहूर्तों की ताकत दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

पिता कौन? मनीर अहमद या सलीम-फाइलों की कहानी अलग-अलग वर्गों ?

शिकायत के अनुसार, बिहार के रिकॉर्ड में एहसान अहमद के पिता का नाम मनीर अहमद बताया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के कुछ दस्तावेजों में कथित तौर पर पिता का नाम सलीम दर्शाया गया, व्यंग्य यही है कि आम नागरिक अपने नाम की एक स्पेलिंग सुधारने के लिए महीनों सरकारी दफतरो के चक्कर काटता है, लेकिन यहां आरोप है कि पूरा पारिवारिक इतिहास ही अपडेट हो गया और सिस्टम शायद छुट्टी पर चला गया, क्या सरकारी फाइलें अब सोशल मीडिया प्रोफाइल बन गई हैं, जहां रिश्ते भी एडिटेड और पहचान भी रीसेट हो जाती है?

जाति प्रमाण-पत्र: नियम किताबों में सख्त, फाइलों में नरम?

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय निवासी सलीम (पिता-गुलबहार) के रिकॉर्ड के आधार पर कथित तौर पर ओबीसी जाति प्रमाण-पत्र हासिल किया गया, अगर यह जांच में सही साबित होता है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया की परीक्षा बन जाएगी, व्यंग्य में कहें तो लगता है जैसे नियम सिर्फ नोटिस बोर्ड पर सख्त हैं, लेकिन फाइलों में आते-आते मुलायम हो जाते हैं।

निवास प्रमाण-पत्र: नया पत्र, नई पहचान और सिस्टम की पुनर्नी अदत

शिकायत के अनुसार मूल निवास बिहार होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण-पत्र तैयार हुआ, अब सवाल यह है—क्या सत्यापन सिर्फ कागज देखने तक सीमित रह गया है? आम नागरिक से बिजली बिल, पानी बिल और पञ्जोमी की गवाही तक मांगी जाती है, लेकिन यहां आरोप

है कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया जैसे सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांध रखी हो।

अरमान अहमद का मेडिकल एडमिशन—मेहनत की जीत या दस्तावेजों की स्पीड?—

आरोपों के मुताबिक, इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अरमान अहमद को नीट-2022 काउंसलिंग के जरिए कांकेर मेडिकल कॉलेज में ओबीसी श्रेणी में प्रवेश मिला, मेडिकल सीट

सिस्टम की भूमिका: जांचकर्ता या गूक दर्दक?

इस पूरे मामले में शिकायतकर्ताओं ने कई स्तरों पर जांच की मांग की है, जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी, निवास प्रमाण-पत्र सत्यापन करने वाले कर्मचारी, मेडिकल काउंसलिंग अथॉरिटी और कॉलेज प्रशासन, अगर हर स्तर पर दस्तावेज पास हुए, तो या तो सिस्टम बेहद भरोसेमंद है... या फिर बेहद भरोसे में, व्यंग्य में कहें तो सरकारी मुहूर्त शायद इतनी व्यस्त हो गई है कि सवाल पूछने का समय ही नहीं बचा।

डॉक्टर बनने से पहले दस्तावेजों का इलाज जरूरी

फिलहाल यह मामला आरोपों और शिकायतों के दायरे में है, अंतिम सच्चाई जांच से ही सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि अगर कागजों से पहचान बदलने लगे, तो नियम सिर्फ किताबों में रह जाएंगे, जब फाइलें टूटने लगे और जांच सौ जाए, तो मेडिकल सीट भी व्यंग्य बन जाती है।

लाखों छात्रों के सपनों का मंच होती है, ऐसे में अगर आरोप सही निकले, तो यह सिर्फ एक एडमिशन नहीं बल्कि उन छात्रों के साथ अन्याय माना जाएगा जो नियमों पर भरोसा करते हैं, व्यंग्यात्मक सवाल यही है क्या अब मेरिट लिस्ट से ज्यादा ताकत 'डॉक्यूमेंट लिस्ट' की हो गई है?

दस्तावेजों का खेल या सिस्टम की चुप्पी? आरोपों ने मेडिकल एडमिशन पर खड़े किए बड़े सवाल

छत्तीसगढ़ में मेडिकल एडमिशन से जुड़ा

विवाद अब खुलकर सामने आ गया है, इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक तिवारी द्वारा की गई शिकायत ने प्रशासनिक फाइलों की नींद उड़ा दी है, शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि एहसान अहमद और उनके पुत्र अरमान अहमद से जुड़े कुछ दस्तावेजों में कथित बदलाव हुए, जिनके आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया गया, हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने आरोपों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सवाल इतने तीखे हैं कि सिस्टम की भूमिका भी अब चर्चा के केंद्र में आ गई है।

अभिषेक तिवारी की शिकायत 'फाइलों में दो पिता कैसे?'

शिकायतकर्ता अभिषेक तिवारी का दावा है कि बिहार के रिकॉर्ड में जहां पिता का नाम मनीर अहमद बताया जाता है, वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ दस्तावेजों में कथित तौर पर सलीम नाम सामने आता है, व्यंग्यात्मक अंदाज में लोग पूछ रहे हैं क्या सरकारी रिकॉर्ड अब मोबाइल ऐप की तरह हो गए हैं, जहां रिश्ते भी अपडेट और पहचान भी एडिटेड हो जाती है?

जाति प्रमाण-पत्र पर सवाल नियम सख्त या मुहूर्ते तेज?

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्थानीय निवासी सलीम (पिता-गुलबहार) के दस्तावेजों के आधार पर कथित तौर पर ओबीसी जाति प्रमाण-पत्र हासिल किया गया, अगर यह जांच में सही पाया जाता है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहेगा— बल्कि आरक्षण प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन दोनों पर बड़ा सवाल बन जाएगा, व्यंग्य में कहें तो नियम किताबों में सख्त हैं, लेकिन फाइलों में आते-आते शायद नरम पड़ जाते हैं।

मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत सिंहदेव के नेतृत्व में पदयात्रा उदयपुर-लखनपुर में ग्रामीणों संग कांग्रेस ने निकाली यात्रा, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान 'मनरेगा बचाओ संघर्ष' के तहत शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में उदयपुर में लखनपुर विकासखंड में पदयात्रा निकाली गई। पहला चरण उदयपुर ब्लॉक के ग्राम दावा से शुरू लेकर मनोहरपुर, विशुनपुर, मुगाखंड, डुमरखीह होते हुए उदयपुर में समाप्त हुआ। इस दौरान मनरेगा को बहाल करने और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। दूसरा चरण लखनपुर ब्लॉक में ग्राम कोसगा से ग्राम बंधा तक लगभग 3 किमी की पदयात्रा के रूप में आयोजित हुआ। दोनों यात्राओं में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे।

मनरेगा समाप्त करने का आरोप

सभा को संबोधित करते हुए टी.एस. सिंहदेव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी लोककल्याणकारी योजना को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण मजदूरों को उनके क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देती है और संकट के समय लोगों के लिए सहाय्य बनी थी। उन्होंने मांग की कि मनरेगा को पुनः प्रभावी किया जाए और मजदूरी दर 400 रुपये प्रतिदिन की जाए।

ट्रेड डील पर भी जताई विंता

मीडिया से बातचीत में सिंहदेव ने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे देश के किसानों को नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर भी सवाल उठाए।

कई नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद

पदयात्रा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, संभागीय प्रभारी जे.पी. श्रीवास्तव, डॉ. प्रेमसाय सिंह, विक्रमादित्य सिंहदेव, ओमप्रकाश सिंह, अमित सिंहदेव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हनुमान मंदिर दानपेटी चोरी में तीन नाबालिग पकड़ाए

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टरेट परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के दानपेटी से नगद राशि चोरी के मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों को पकड़ा है। घटना 4 फरवरी को दरम्यानी रात की है। पुलिस को पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने बताया कि वे अज्ञानता और जिज्ञासा के कारण मंदिर में घुसे थे। दानपेटी खोलने पर कुछ नगद राशि मिली, जिसे उन्होंने खर्च कर दिया। कोतवाली पुलिस ने तीनों को बाल संप्रेशन गृह भेज दिया है।



देव होटल के पास दो राउंड फायरिंग, आरोपी फरार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के देव होटल के पास शुक्रवार शाम गोली चलने की घटना अब सही पाई गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे अफवाह बताया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान दो राउंड फायरिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार होटल संचालक के भतीजे हनि सिंह ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। घटना के बाद से आरोपी शनिवार सुबह से फरार है। एडिशनल एसपी अमोलक सिंह हिल्लोने ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे देव होटल के पास गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सीएसपी राहुल



बंसल, गांधीनगर थाना और कोतवाली में हनि सिंह और उसके परिजनों ने घटना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती पूछताछ से इनकार किया, जिससे पुलिस को मामला

अफवाह प्रतीत हुआ। हालांकि, आसपास के लोगों ने पटाखे जैसी तेज आवाज सुनने की बात कही, जिसके बाद संदेह गहराया और जांच आगे बढ़ाई गई। जांच में होटल गेट के पास दो राउंड फायरिंग की पुष्टि हुई। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25-27 एवं 125 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुराना विवाद बना कारण

पुलिस के अनुसार हनि सिंह का एक व्यक्ति से पुराना विवाद चल रहा है। करीब 10 से 15 दिन पहले भी दोनों के बीच होटल के पास मारपीट हुई थी। उस समय दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई

थी, केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे हनि सिंह अपने साथियों के साथ कार से पीजी कॉलेज की ओर गया था। इसी दौरान दूसरे गुट के लोगों ने उसकी कार को ओवरटेक कर डंडा फेंका और पीछा करते हुए देव होटल तक पहुंच गए। इसी दौरान आरोपी ने फायरिंग की।

तीन संदेही हिरासत में, हथियार जब्त

घटना के दूसरे दिन पुलिस ने फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। होटल में उधरे तीन संदेहियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने होटल बन से एक एयरगन जब्त की है। सुर्खों के अनुसार 4 से 5 लाइसेंसी बंदूकें भी जब्त की गई हैं।

क्रिकेट में विदेश दौरे का झांसा देकर 15.38 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार फर्जी दस्तावेज बनाकर खिलाड़ी से ऑनलाइन वसूली, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

देश-विदेश में क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाने का झांसा देकर एक खिलाड़ी से 15 लाख 38 हजार रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुमूंक सिन्हा (40 वर्ष), निवासी त्रिकोण चौक, अम्बिकापुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी अजय कुमार वर्मा (निवासी हरदोई, उत्तरप्रदेश) की मुलाकात वर्ष 2021 में नेपाल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने खुद को क्रिकेट संघ से जुड़ा बताते हुए विदेशी टूर्नामेंट में खेलने का लालच दिया और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे जमा कराना शुरू किया। आरोपी ने चयन व विदेशी दौरे से

जुड़े फर्जी दस्तावेज मोबाइल पर भेजते हुए पेंटीएम, गूगल पे व फोन पे के माध्यम से लगातार रकम वसूल की। इसके बाद प्रार्थी को छत्तीसगढ़ बुलाकर भी अतिरिक्त राशि ली गई। कुल मिलाकर आरोपी ने 15.38 लाख रुपये की ठगी की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर से जानकारी ली, जहां संबंधित क्रिकेट संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं होने की पुष्टि हुई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, साइबर सेल प्रभारी अजीत मिश्रा सहित पुलिस टीम सक्रिय रही।



राजीव गांधी कॉलेज की प्राध्यापिका रश्मि कौर को पीएचडी की उपाधि डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में किया तोष



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर के वाणिज्य संकाय में कार्यरत प्राध्यापिका श्रीमती रश्मि कौर को डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में पीएचडी (डॉक्टरेट) की उपाधि प्राप्त हुई है। उनकी इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिवार और शैक्षणिक जगत में हर्ष का माहौल है। रश्मि कौर प्रारंभ से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने गुरु धासीदास विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और वर्ष 2009 में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने एमए (अंग्रेजी) एवं एमए (अर्थशास्त्र) की उपाधियां भी अर्जित की हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण कर मेरिट सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2017 से वे राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवाने दे रही हैं। रश्मि कौर के अब तक 15 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वे कई संगोष्ठियों और सेमिनारों में भी सहभागिता कर चुकी हैं। उनकी इस शैक्षणिक उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य, वाणिज्य संकाय के प्राध्यापक एच.ए. स्टाफ ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है।

घुनघुट्टा डेम में नाव पलटी...मछुआरे की मौत मछली पकड़ते समय पानी में गिरा ग्रामीण, अस्पताल में तोड़ा दम

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र स्थित घुनघुट्टा डेम में शुक्रवार शाम मछली पकड़ने के दौरान नाव अनियंत्रित हो जाने से एक ग्रामीण पानी में गिरकर डूब

गया। अन्य मछुआरों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक विरूच राम (54 वर्ष) ग्राम कलमसा का निवासी था। वह शुक्रवार शाम डेम

में नाव से जाल खलकर मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान पानी से मछली निकालते समय उसकी नाव असंतुलित हो गई और वह पानी में गिर पड़ा। साथ में दूसरी नाव में मछली पकड़ रहे ग्रामीण रामसागर और ब्रम्हदेव ने शोर सुनकर उसे

पानी से बाहर निकाला और डेम किनारे लाया। परिजनों को सूचना देने के बाद घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वसंतोत्सव या प्रशासनिक स्क्रिप्ट? जंगल कैफे उद्घाटन ने खड़े किए नए सवाल सरकारी पैसा,फीता 'विशेष अतिथि' के हाथ-कोरिया में नई परंपरा की शुरुआत?

अजब आयोजन, गजब प्रोटोकॉल! घुघरा कार्यक्रम पर सियासी और प्रशासनिक बहस तेज

- वसंतोत्सव के बहाने उद्घाटन राजनीति? प्रशासन की भूमिका पर उठे बड़े सवाल
- मंच पर बसन्त,पर्दे के पीछे प्रशासन-कोरिया का कार्यक्रम बना चर्चा का केंद्र
- फीता किसका,फैसला किसका? घुघरा में 'जंगल कैफे' से ज्यादा प्रोटोकॉल चर्चा में
- सवाल के बीच वसंतोत्सव- क्या छत्तीसगढ़ में बदल रही है उद्घाटन की परंपरा?
- अजब जिला, गजब उद्घाटन! प्रशासन पीछे, चर्चा आगे
- जंगल कैफे उद्घाटन पर सवाल: बुलावा किसने भेजा, आयोजन किसने साधा?
- बिहान योजना या 'बैकस्टेज मैनेजमेंट'? घुघरा कार्यक्रम पर उठे नए प्रश्न
- महिला समूह की ताकत या प्रशासन की रणनीति-वसन्तोत्सव बना राजनीतिक पहली
- किसके इशारे पर आया काफिला? जंगल कैफे उद्घाटन के पीछे की कहानी चर्चा में

फीता किसने कटवाया? महिला समूह की पहुंच या प्रशासन की चाल?

वसन्तोत्सव के बहाने बड़ा आगमन—कोरिया में 'कौन बुलाया' बना सबसे बड़ा सवाल

बिहान योजना का मंच या सियासी प्रयोगशाला? घुघरा कार्यक्रम पर बहस तेज



—न्यूज डेस्क—
कोरिया, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया जिले में 6 फरवरी को जो कुछ हुआ, उसे वसन्तोत्सव कहा गया, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब अभी भी धुंध में है, कार्यक्रम किसका था, किसने आयोजित किया, प्रशासन की भूमिका क्या थी और आखिर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का आगमन किस आधिकारिक हैसियत से हुआ—यह सब किसी मकड़ी के जाल से कम नहीं लग रहा, कागजों में आयोजन सामाजिक-सांस्कृतिक था, मंच पर महिला समूह का नाम था, लेकिन पर्दे के पीछे प्रशासन की भागदौड़ साफ नजर आई, सवाल यह है कि अगर कार्यक्रम पूरी तरह सामाजिक था तो प्रशासनिक मशीनरी इतनी सक्रिय क्यों दिखी? और अगर सरकारी कार्यक्रम था तो आयोजक के रूप में स्थानीय संगठन को आगे क्यों किया गया? घुघरा का कार्यक्रम पर्यटन और महिला सशक्तिकरण के नाम पर सकारात्मक पहल जरूर हो सकता है, लेकिन पारदर्शिता और प्रोटोकॉल की स्पष्टता उतनी ही जरूरी है, वरना हर बसन्त उत्सव के साथ यह सवाल जरूर उठेगा—यह उत्सव था या प्रशासनिक प्रयोग?

अजब प्रशासन, गजब आयोजन

जिले में चर्चा है कि प्रशासन सामने कम और पीछे ज्यादा सक्रिय रहा, मंच पर महिला समूह, पोस्टर में बसन्त उत्सव, लेकिन व्यवस्थाओं में सरकारी रंग—यह मिश्रण लोगों को उलझा रहा है, कई लोग इसे व्यंग्य में 'प्रशासन की बैकस्टेज बैटिंग' कह रहे हैं—जहां गंद कोई और फेंक रहा है, लेकिन रन किसी और के खाते में जुड़ रहे हैं।

क्या छत्तीसगढ़ में बदल रही है राजनीतिक परंपरा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकारी परियोजनाओं के उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों की जगह उनके परिजन दिखाई देने लगे, तो यह एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत हो सकती है, समर्थक इसे सामाजिक जुड़ाव बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे संस्थागत मर्यादाओं से जुड़ा युवा मान रहे हैं।

सरकार का पैसा, फीता किसी और के हाथ?—घुघरा का 'जंगल कैफे' शासन के पैसों से बना, संचालन महिला समूह को मिला—यह सकारात्मक पहल कही जा सकती है, लेकिन असली बहस इस बात पर है कि सरकारी परियोजना का उद्घाटन किसके हाथों होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में शायद ही ऐसा दृश्य बार-बार देखने को मिला हो कि मुख्यमंत्री या मंत्री के परिजन सरकारी परियोजनाओं का फीता काटते नजर आए हों, अब सवाल उठ रहा है—क्या यह नई परंपरा की

शुरुआत है या फिर स्थानीय स्तर पर लिया गया एक 'अनौपचारिक' निर्णय? प्रोटोकॉल या प्रयोग?—मुख्यमंत्री के परिवार को सुरक्षा प्रोटोकॉल मिलना स्वाभाविक है, लेकिन क्या उसी प्रोटोकॉल के दायरे में सरकारी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनना भी शामिल है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि प्रशासन ने आलोचना से बचने के लिए कार्यक्रम को वसन्त उत्सव का नाम दिया, जबकि असल फोकस उद्घाटन पर ही रहा, सवाल यह भी है कि क्या यह 'साफ्ट लॉन्च'

वसन्तोत्सव या सवालों का मौसम?

वसन्तोत्सव का उद्देश्य प्रकृति और संस्कृति से जुड़ना था, लेकिन कोरिया में यह आयोजन सवालों के मौसम में बदल गया, कौन आयोजक था, किसने निर्णय लिया और प्रशासन की वास्तविक भूमिका क्या रही, इन सवालों का जवाब जितना देर से मिलेगा, चर्चाएं उतनी ही तेज होती जाएंगी।

आयोजन सामाजिक बताया गया, तस्वीरों में दिखा पूरा प्रशासन

घुघरा में आयोजित वसन्तोत्सव और 'जंगल कैफे' उद्घाटन कार्यक्रम को भले ही किसी संगठन द्वारा आयोजित बताया गया हो, लेकिन कार्यक्रम की तस्वीरों और व्यवस्थाओं ने इसे पूरी तरह शासकीय आयोजन जैसा बना दिया, कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की सक्रियता इतनी थी कि आयोजन में किसी भी तरह की कमी न दिखे, इसका पूरा ध्यान रखा गया।

था या 16 फरवरी को संभावित मुख्यमंत्री दौर से पहले माहौल बनाने की रणनीति? मंच संचालन के लिए आत्मानंद विद्यालय की शिक्षिका को मिली अनुमति—कार्यक्रम का मंच संचालन आत्मानंद विद्यालय की एक शिक्षिका ने किया, जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई थी, बताया जाता है कि उक्त शिक्षिका कई शासकीय आयोजनों में मंच संचालन करती रही हैं। हालांकि यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि

कार्यक्रम पूरी तरह सामाजिक स्वरूप का था और मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई थीं, तो फिर सरकारी शिक्षिका को आधिकारिक अनुमति देकर मंच संचालन क्यों कराया गया। महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को?—स्थानीय चर्चाओं के अनुसार जिले के कई गांवों से महिलाओं को कार्यक्रम स्थल तक लाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपी गई थी। अगर यह

दावा सही है, तो आयोजन में प्रशासनिक भूमिका और अधिक स्पष्ट नजर आती है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

प्रशासनिक सहयोग पर उठे सवाल—कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं कंवर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, सवाल यह उठ रहा है कि यदि वह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, तो प्रशासनिक स्तर पर इतनी व्यापक व्यवस्था क्यों की गई, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ऐसे आयोजनों में प्रोटोकॉल और प्रशासनिक सीमाओं की स्पष्टता जरूरी होती है, ताकि भ्रम की स्थिति न बने।

जंगल कैफे और बिहान योजना का 'नया प्रयोग'—आयोजन का मुख्य उद्देश्य जंगल कैफे का उद्घाटन बताया गया, जो शासन की योजनाओं से तैयार हुआ है और जिसके संचालन की जिम्मेदारी महिला समूह को दी गई है। जिले में चर्चा है कि यह पहल बिहान कार्यक्रम के तहत एक नया प्रयोग है, जिसे पर्यटन और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम के स्वरूप और प्रशासनिक भूमिका को लेकर सवालों का दौर जारी है।

क्षेत्रीय विधायक प्रबोध मिंज ने पण्डो समाज के साथ की भेंट मुलाकात, जमीन विवाद पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया

—संवाददाता—
लखनपुर, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रबोध मिंज ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत माजा के आश्रित ग्राम राजकटेल में पण्डो समाज के लोगों से मुलाकात की विधायक ने ग्रामीणों का कुशल-क्षेम जाना और उनकी समस्याओं को सुना। पण्डो समाज के लोगों ने बताया कि वे कई पीढ़ियों से यहां निवासरत हैं और उनकी जमीन के कागजात उनके नाम पर हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर घर बना लिए हैं तथा खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इससे उन्हें जीवन-यापन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों ने कुछ दिनों पूर्व इस संबंध में कलेक्टर सरगुजा को भी शिकायत की थी। विधायक प्रबोध मिंज ने मौके पर ही एसडीएम से चर्चा की और त्वरित



निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने जमीन वापस दिलाने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा, ग्रामीणों की मांग पर चबूतरे में शोध निर्माण की घोषणा भी की। इस पहल से पण्डो समाज के प्रमुखों ने विधायक महोदय का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मण्डल अध्यक्ष रवि महंत, पूर्व मण्डल अध्यक्ष अजीत सिंह, महामंत्री विक्रम सिंह, सरपंच खेमराज सिंह, प्रवीण

यादव, जमुना प्रसाद, पण्डो समाज के अध्यक्ष एवं ग्रामीण रामधन पण्डो, दरोगा पण्डो, रतन पण्डो, लालगुलाब पण्डो, सनमान पण्डो, हृदय पण्डो, पहलवान पण्डो, मुन्ना पण्डो, तिजो बाई पण्डो, मिनसरो पण्डो, फुलसुंदरी पण्डो, मनासो पण्डो सहित समाज के अन्य प्रमुख सदस्य और भारी संख्या में पण्डो समाज के लोग उपस्थित रहे। यह मुलाकात पण्डो जनजाति की भूमि सुरक्षा और विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुई है।

'मजबूत कानून, सुरक्षित अधिकार' के संदेश के साथ वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 का व्यापक प्रचार-प्रसार जिले के सभी ग्राम पंचायत में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का संयुक्त आयोजन

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत हरॉटिकरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 'मजबूत कानून, सुरक्षित अधिकार' के संदेश के साथ वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। जिले में नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देने, जनजागरूकता बढ़ाने तथा शासन की योजनाओं से जोड़ने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वीबी-जी राम जी अधिनियम से संबंधित जागरूकता पंपलेट का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत हरॉटिकरा की सरपंच श्रीमती अमृता पैकरा ने



कहा कि हमारे गांव में आज रोजगार दिवस और आवास दिवस एक साथ मनाया गया। वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई और पंपलेट वितरित किए गए। रोजगार दिवस के अवसर पर लोगों को 100 नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार के प्रावधान के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि गांव का हर पात्र परिवार योजनाओं का पूरा लाभ ले और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निर्माण

जुड़ सके। रोजगार दिवस पर जी राम जी अंतर्गत कार्यों, मजदूरी भुगतान एवं रोजगार मांग पंजीयन की प्रक्रिया समझाई गई। आवास दिवस के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्वीकृत आवसों की प्रगति की समीक्षा कर हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में आवस पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया गया। लंबित किरतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए केवाईसी पूर्ण करने और 7 दिवस के भीतर किरत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निर्माण

कार्य में आ रही तकनीकी व सामग्री संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु हितग्राहियों, स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय भागीदारों के साथ चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के टोल फ्री नंबर 1800-233-1290 की जानकारी भी दी गई, ताकि हितग्राही अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संपर्क कर सकें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

खुद को बेटे का परिचित बताकर बुजुर्ग किसान से हजारों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

—संवाददाता—
राजपुर, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस ने दिनदहाड़े एक ग्रामीण कृषक से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। सहकारी बैंक से रुपये निकालकर घर लौट रहे एक बुजुर्ग किसान को झूसे में लेकर 49 हजार रुपये की ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। पुलिस एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने

बताया कि 02 फरवरी 2026 को ग्राम डंडखडुआ निवासी प्रार्थी निबल साय अपने बेटे के साथ सहकारी बैंक राजपुर से धन बिक्री की रकम निकालने आया था। बैंक से 49,000 रुपये नकद प्राप्त करने के बाद वह अपने बेटे का इंतजार करता रहा। बेटे के नहीं लौटने पर वह पैदल अपने गांव की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवक उससे मिले। तंबाकू भांगने और बेटे को पहचानने का नाटक कर आरोपियों ने उसे गांव तक छोड़ने का झूसा दिया। प्रार्थी के सीधेपन का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने उससे तैलिये में बंधे 49 हजार

रुपये मांगे और कुछ दूरी तक मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए। बाद में दुकान से सामान लेने का बहाना बनाकर वे रुपये लेकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट बाद में थाना राजपुर में दर्ज कराई गई। मामले की पहचान की गई। फुटेज के आधार पर आरोपी जेल कुमार पिता रामलाल (27 वर्ष), निवासी ग्राम तुंगा, थाना लखनपुर, जिला सरगुजा को विन्हीत कर गिरफ्तार किया गया। पुछताछ में आरोपी ने

अपने साथी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। पुलिस एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी की पतासाजी में आरक्षक अमित राजवाड़े की विशेष भूमिका रही। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी राजपुर भारद्वाज सिंह के साथ सहायक उप निरीक्षक अशोक तिकी, प्रधान आरक्षक पवन सिंह एवं प्रभान आरक्षक राजेंद्र ध्रुव सक्रिय रूप से शामिल रहे।



विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता बजट : विधायक भइयालाल राजवाड़े

भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी की उपस्थिति में बजट की उपलब्धियों पर विशेष प्रेस वार्ता

-संवाददाता-
कोरिया, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक भइयालाल राजवाड़े ने बजट को ऐतिहासिक और समावेशी-बताते हुए कहा कि यह किसान, महिला, युवा और व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को तकनीकी रूप से सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



व्यापारियों और मध्यम वर्ग को राहत

व्यापारियों और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए कई आर्थिक फैसलों का उल्लेख किया गया, छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (MAT) घटाकर 14 प्रतिशत किया गया, तैदूपत्ता पर TCS घटाकर 2 प्रतिशत करने से छत्तीसगढ़ के संग्राहकों को लाभ, विदेश यात्रा और शिक्षा पर TCS 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का निर्णय।

कांग्रेस बनाम मोदी सरकार-विकास के आंकड़े

प्रेस वार्ता के दौरान विधायक राजवाड़े ने पूर्व सरकारों और वर्तमान बजट आवंटन की तुलना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विकास की गति को कई गुना बढ़ाया है, उन्होंने बताया कि 7 नए रेलवे कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग और 4000 इलेक्ट्रिक बसें जैसी योजनाएं आधुनिक भारत की नई तस्वीर पेश करेंगी, उन्होंने कहा, यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने वाला बजट है।

मंत्रालय/क्षेत्र	कांग्रेस सरकार (पुराना बजट)	मोदी सरकार (बजट 2026)
शिक्षा	₹39,000 करोड़	₹1.39 लाख करोड़+
रक्षा	₹2 50 लाख करोड़	₹7.50 लाख करोड़+
स्वास्थ्य	₹38,000 करोड़	₹1.00 लाख करोड़+
किसान	₹29,000 करोड़	₹1.62 लाख करोड़+
रेलवे	₹29,000 करोड़	₹2.81 लाख करोड़+
पूंजीगत व्यय (Capex)	₹2.00 लाख करोड़	₹12.2 लाख करोड़
राज्यों को मदद	₹5.00 लाख करोड़	₹26.72 लाख करोड़



किसानों और पशुपालकों के लिए 'सौगातों का पिता'

विधायक राजवाड़े ने कहा कि छोटे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, पशुपालकों के लिए लोन सब्सिडी तथा निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा कॉलेजों हेतु फ्रेंडली-लैंड सहायता का ऐलान, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में 500 बड़े तालाबों व अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की योजना, अखरोट, बादाम, कोको और नारियल किसानों के लिए विशेष बागवानी पैकेज, किसानों को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से नई योजनाओं की शुरुआत।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फोकस-भारत बनेगा 'बायो फार्मा हब'

उन्होंने कहा कि आम जनता को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बजट में कई अहम प्रावधान किए गए हैं, कैंसर की 17 गंभीर दवाओं पर आयात शुल्क खत्म कर इलाज सस्ता करने का प्रयास, देश में 5 नए रीजनल मेडिकल हब स्थापित करने की योजना, बुजुर्गों की देखभाल के लिए 1.5 लाख मल्टी-स्कैलड केयर-टेकर्स का प्रशिक्षण, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना से आयुष क्षेत्र को बढ़ावा।

महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण

विधायक ने कहा कि बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कई पहल की गई हैं, ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए SHE-मार्ट की घोषणा, जिससे उन्हें बाजार उपलब्ध होगा, लखपति दीदी योजना का विस्तार कर अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य, शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप और उच्च स्तरीय शिक्षण समितियां।

वे रहे उपस्थित...

इस अवसर पर विधायक भइयालाल राजवाड़े, जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, जिला उपाध्यक्ष बसंत राय, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, कपिल जायसवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह, जिला मंत्री शारदा गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी तीर्थ राजवाड़े, जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी राकेश गुप्ता, युवा मोर्चा जिला महामंत्री मनोज साहू, पार्षद रेखा वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष सुनील सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सिरपुर महोत्सव में मनेंद्रगढ़ की बेटी जसमीत कौर सम्मानित

जसगीत गायिका को 'छत्तीसगढ़ रत्न' सम्मान, भजनों की प्रस्तुति से गूँज उठा मंच



भजनों की प्रस्तुति ने बांधा समां

सिरपुर महोत्सव में बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ के कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच दिया गया। इसी कड़ी में जसमीत कौर ने जसगीत और भक्ति गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी मधुर आवाज और पारंपरिक शैली ने सांस्कृतिक आयोजन को नई ऊँचाई दी।

'छत्तीसगढ़ रत्न' से सम्मानित, मिला आशीर्वाद

कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की, माननीय विधायक राजू सिन्हा और कलेक्टर विनय लहरो ने जसमीत कौर के गीतों को सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही जसगीत गायिका को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से भी नवाजा गया, जो क्षेत्र के लिए गर्व की बात मानी जा रही है।

-संवाददाता-
एमसीबी, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव में इस वर्ष सांस्कृतिक रंगों के बीच मनेंद्रगढ़ की बेटी के नाम से प्रसिद्ध जसगीत गायिका सुश्री जसमीत कौर ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। महोत्सव के दूसरे दिन उनके

भजनों और जसगीतों की प्रस्तुति ने पूरे मंच को भक्ति और लोक-संगीत के रंग में रंग दिया, जहां दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गुंती रही, सिरपुर महोत्सव में जसमीत कौर की प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती, मनेंद्रगढ़ की यह बेटी लगातार अपने गीतों से न केवल मंचों को सजा रही है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन कर रही है।

कम उम्र में बड़ी पहचान

कम उम्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जसमीत कौर अब तक कई पुरस्कार और सम्मान अपने नाम कर चुकी हैं, मनेंद्रगढ़ से निकलकर प्रदेश और देश स्तर पर अपनी आवाज का जादू बिखेर रही इस युवा कलाकार को लेकर एमसीबी जिले के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे शहर से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा है।

जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं

मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्याम बिहारी जायसवाल ने भी जसमीत कौर को एमसीबी जिले की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।



जशपुर के 12 युवाओं का अर्धसैनिक बलों में चयन

-संवाददाता-
जशपुरनगर, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर रोहित व्यास एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में संचालित नव संकल्प शिक्षण संस्थान ने एक बार फिर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्ष 2025 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कांस्टेबल जनरल ड्यूटी (एसएससी जीडी) परीक्षा के माध्यम से संस्थान के कुल 12 छात्र-छात्राओं का चयन विभिन्न अर्धसैनिक बलों में हुआ है।

ने बताया कि एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में आयोजित की गई थी, जिसमें नव संकल्प शिक्षण संस्थान के 36 छात्र सफल हुए थे। इसके पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मेडिकल परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में सम्पन्न हुए। सभी चरणों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद हाल ही में घोषित अंतिम परिणाम में संस्थान के कुल एक दर्जन विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की। चयनित विद्यार्थियों में 5 का चयन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), 3 का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), 2 का सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), 1 का भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) तथा 1 का सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में हुआ है। चयनित विद्यार्थियों में बालेश्वर नाग, नोवेल टोप्यो, सोनेश्वर प्रधान, नेहरू लाल एवं अरुण कुमार पैकरा का चयन सीआइएसएफ में हुआ है। बिन्देश्वर एवं सृष्टि तिकी बीएसएफ में चयनित हुए हैं। वहीं रोहित केरकेट्ट, अरविंद केरकेट्ट एवं सुरेन्द्र राम का चयन सीआरपीएफ में हुआ है। देव प्रसाद नाग का चयन एसएसबी तथा चन्दन कालो का चयन आईटीबीपी में हुआ है।

शहर के वरिष्ठ समाजसेवी का निधन



-संवाददाता-
सूरजपुर, 07 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर के मेन रोड निवासी वरिष्ठ समाजसेवी 73 वर्षीय रामस्वरूप गुप्ता का रायपुर एम्स में उपचार के दौरान दुःखद निधन हो गया। उनके निधन की खबर से शहर सहित समाज में शोक की लहर दौड़ गई। वे लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और क्षेत्र में अपनी सादगी एवं सेवा भाव के लिए जाने जाते थे।

नमदगिरी रेणुदी तट मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार

स्वर्गीय रामस्वरूप गुप्ता का पार्थिव शरीर शनिवार को सूरजपुर स्थित नमदगिरी रेणुदी तट मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन किया गया। अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में परिजन, मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता और शहरवासी उपस्थित रहे तथा नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

शोककुल परिवार

स्वर्गीय गुप्ता मन्नु गुप्ता एवं मनोज गुप्ता के पिता थे। वे रामकिशन गुप्ता, राम सजीवन गुप्ता और संतोष गुप्ता के भाई तथा जितेंद्र गुप्ता के बड़े पिताजी थे। उनके निधन से परिवार सहित समाज में गहरा शोक व्याप्त है।

सामाजिक क्षेत्र में रहा सक्रिय योगदान

रामस्वरूप गुप्ता अपने मिलनसार स्वभाव और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते थे, उनके निधन पर शहर के कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, (E&M) DIVISION
PUBLIC HEALTH ENGG. DEPT. AMBIKAPUR (C.G.)

No/190/2025-2026/TS/E.E./E&M/Dn./
P.H.E.D./Ambikapur Date 05.02.2026

Notice Inviting Tender NIT No. 08/2025-26(2nd Call)

Sealed tenders are invited on behalf of Governor of Chhattisgarh on Form "C" for Supply work carried out as mentioned below from the manufacturer or their authorized dealers having experience to do such type of work.

S.No.	Brief Description of Materials	Qty
01	Supply of Drill Rod Suitable for hydraulically operated DTH Drilling unit having following specification 15 Feet long drill rods having OD 88.90 mm and thickness (Minimum 10.5 mm) made out of 155 Seamless pipe friction welding and induction hardening is to be provided for drilling 150 to 180 mtrs. Deep holes: Flush hole dia should be 36 mm with adopter 2.3/8" 4 TPI API thread made out of E-19 steel having each dirll rod approximate weight 86 kg 2% + Grade of pipe JSL 155 HT.	40 Nos

Note:- 01. Cost of Tender From -750-00
02. Estimated Cost (In Rs.) :- 835440.00
03. Earnest Money (In Rs.) :- 8400.00
04. Bid Submission Date :- 07/02/2026 to 18/02/2026
04. Terms of tender and details of material can be seen in the office during office hours.
05. Conditional tender will not be accepted.
Executive Engineer (E&M) PHED Division Ambikapur (C.G.)

जो नंबर-252606511/2
Executive Engineer (E&M) PHED Division Ambikapur (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कुन्कुरी जिला - जशपुर (छ.ग.)

निविदा निरस्तीकरण आदेश

आदेश क्र 188 व.ले.लि./2025-26/कुन्कुरी दिनांक 03/02/2026

मुख्य अभियंता (निविदा प्रकोष्ठ) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) के पत्र पृ. क्रमांक 4263936 / निविदा प्रकोष्ठ / 2025 / 3429 (TC) नवा रायपुर, दिनांक 23.12.2025 के परिपालन में निविदा सूचना क्र. 03 / व.ले.लि. / 2025-26 दिनांक 26.11.2025 (प्रथम आमंत्रण) निविदा सिस्टम क्रमांक 180420 (जी - 252605087) केराकछर जलाशय योजना के नहरों में 08 नग संरचनाओं का निर्माण एवं पुनर्निर्माण, केनाल बैंक प्रोटेक्शन कार्य, मुख्य तथा माईन नहरों में सी.सी. लाईनिंग कार्य एवं मुख्य एवं शाखा नहरों का रिसेक्सनिंग कार्य राशि रु. 550.97 लाख हेतु निविदाकार की संख्या निरंक होने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, कुन्कुरी (छ.ग.)
कुन्कुरी - मुख्य अभियंता हसदेव गंगा
कछर जल संसाधन विभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)
जो नंबर-252606477/6

उत्सव के बीच गुहार! पांच माह से मानदेय को तरसती मितानिनों ने सीएम की पत्नी कौशिल्या साय को सुनाई त्रथा

मैडम अब घर चलाना मुश्किल... मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगा जल्द समाधान

वया बोलीं मितानिन बहनें...

हम पांच महीने से खाली हाथ सेवा दे रहे हैं। घर की स्थिति खराब हो चुकी है, हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी त्रथा समझेगे और जल्द राहत देंगे। - सुंदरकली तिकी व सोनमती साहू, मितानिन समन्वयक

सवालों के घेरे में व्यवस्था... वसन्तोत्सव जैसे उत्सवी माहौल में उठी यह गुहार अब प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी मानी जाने वाली मितानिनों को समय पर मानदेय न मिलना स्वास्थ्य तंत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा को जन्म दे रहा है।

-संवाददाता- कोरिया, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

क्षेत्र में आयोजित 'बसन्तोत्सव' कार्यक्रम उस समय अचानक चर्चा का केंद्र बन गया, जब खुशियों और सांस्कृतिक रंगों के बीच स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों ने अपनी आर्थिक पीड़ा को सार्वजनिक मंच तक पहुंचा दिया। मानदेय भुगतान को लेकर संघर्ष कर रही मितानिन ब्लॉक समन्वयकों ने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशिल्या साय को

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं का समाधान कराने की गुहार लगाई, भावुक अंदाज में मितानिनों ने कहा - मैडम, अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी समस्या का समाधान जरूर करवाइयेगा। उत्सव के रंगों के बीच उठी मितानिनों की यह आवाज अब शासन-प्रशासन के लिए एक अहम संदेश बन गई है, देखना होगा कि उनकी गुहार कितनी जल्दी फैसलों तक पहुंचती है और कब तक उनके रुके हुए मानदेय का इंतजार खत्म होता है।



मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाईये हमारी आवाज-भावुक अपील

श्रीमती कौशिल्या साय से मुलाकात के दौरान मितानिनों ने कहा कि वे गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन आज खुद अपने परिवार को जख्मतें पूरी करने में असमर्थ हो रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री की पत्नी के माध्यम से उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और जल्द राहत मिलेगी।

चार दिन पहले CMHO को भी सौंपा था आवेदन

यह विरोध अचानक नहीं था। जानकारी के अनुसार, मितानिन ब्लॉक समन्वयकों ने महज चार दिन पहले ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को लिखित आवेदन देकर भुगतान की मांग की थी। लेकिन विभागीय स्तर पर तोस आश्वासन नहीं मिलने से उन्होंने बसन्तोत्सव में पहुंचे अतिथि के सामने अपनी बात रखने का फैसला किया।

आर्थिक तंगी से जूझ रही स्वास्थ्य सेवा की आधारशिला

मितानिन ब्लॉक समन्वयक सुंदरकली तिकी और सोनमती साहू के नेतृत्व में पहुंची मितानिनों ने बताया कि वे पिछले पांच महीनों से बिना मानदेय के लगातार सेवा दे रही हैं, कोविड काल से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति अब गंभीर हो चुकी है, उनका कहना है कि नियमित भुगतान नहीं होने से परिवार चलाना तक मुश्किल हो गया है और कई मितानिन मानसिक तनाव से गुजर रही हैं।

ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें...

- वकाया मानदेय: ब्लॉक समन्वयक, हेल्प डेस्क मितानिन और स्वास्थ्य पंचायत समन्वयकों को पांच माह से भुगतान नहीं।

- कम राशि और अस्पष्ट जानकारी: केंद्रांश और राज्यांश की राशि बेहद कम मिलने तथा किस मद से कितना भुगतान हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

- मानसिक दबाव: बिना वेटन लगातार सेवा देने से मितानिनों में भारी रोष और मानसिक तनाव।

पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

सूरजपुर एफटीसी न्यायालय का फैसला - धारा 302 से घटकर धारा 304 (भाग-1) में दोषी ठहराया, 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया घर के किचन में मिली थी महिला की लाश, पति या फरार



-संवाददाता- सूरजपुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में वर्ष 2023 में सामने आए एक चर्चित हत्या प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2023 को कॉलेज रोड सूरजपुर निवासी बबिता ने थाना सूरजपुर में सूचना दी थी कि वह सुबह धनराज उर्फ निशा सिंह के घर सुना मांगने गई थी। घर के बाहर से आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिलने पर वह अंदर गई, जहां किचन कमरे में महिला कंबल से ढकी हुई मिली। कंबल हटाने पर महिला मृत अवस्था में पाई गई, जबकि उसका पति रामरतन देवांगन घर में मौजूद नहीं था।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को किया था गिरफ्तार

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 39/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपी रामरतन देवांगन (30 वर्ष), निवासी ग्राम सुरता छतापारा, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया गया। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक एसआई दिनेश राजवाड़े द्वारा की गई, जिन्होंने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने बदली धारा, गैर इरादतन हत्या माना अपराध

प्रकरण की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) श्री मानवेन्द्र सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों, परिस्थितियों और मृतिका को लगी चोटों की प्रकृति का परीक्षण करने के बाद यह पाया कि मामला हत्या (धारा 302) का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-1) का बनता है।

10 वर्ष की कठोर कारावास और अर्थदंड

दिनांक 31 जनवरी 2026 को सुनाए गए निर्णय में न्यायालय ने आरोपी रामरतन देवांगन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (प्रथम भाग) के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है।

न्यायालय के फैसले से मामले का पताक्षेप

करीब तीन वर्ष तक चले इस मामले में न्यायालय के फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जिससे लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण का न्यायिक निष्कर्ष सामने आया।

वकीलों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भड़का जिला अधिवक्ता संघ सोशल मीडिया वीडियो को लेकर थाने में दी गई तहरीर

पुलिस से की गई मांग तत्काल FIR और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई

अधिवक्ता संघ ने पुलिस को दिए गए पत्र में स्पष्ट रूप से मांग रखी है कि- दोनों आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए, वीडियो को हटाने और भविष्य में इस तरह की सामग्री प्रसारित होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, संघ का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इससे कानून व्यवस्था और अधिवक्ता समुदाय की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पुलिस जांच में जुटी, सभी पहलुओं की होगी पड़ताल

सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता, संदर्भ और उसमें की गई टिप्पणियों की कानूनी स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।



-संवाददाता- मनेन्द्रगढ़, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिला अधिवक्ता संघ मनेन्द्रगढ़ ने सोशल मीडिया पर वकीलों के विरुद्ध कथित अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित किए जाने के मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया है, संघ ने सिटी कोतवाली प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है, शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित वीडियो व तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

'दस्तक' चैनल संचालक और रघुनाथ पोद्दार पर गंभीर आरोप - आईटी एक्ट सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग, पुलिस जांच में जुटी

आगे क्या ?

अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है, यदि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस मामले को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है और गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कृत्य का विरोध जारी रहेगा।



रघुनाथ पोद्दार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम पेशे की गरिमा-शुरू हुई नई बहस

इस घरे घटनाक्रम के बाद मनेन्द्रगढ़ में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी बहस छिड़ गई है, एक ओर अधिवक्ता संघ पेशे की गरिमा की रक्षा की बात कर रहा है, वहीं कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर बढ़ती बयानबाजी का परिणाम बता रहे हैं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयान यदि किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, तो कानून के तहत कार्रवाई संभव है।

13 मिनट का वीडियो बना विवाद का केंद्र

अधिवक्ता संघ के अनुसार लगभग 13 मिनट लंबे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और साझा किया। संघ का कहना है कि इस तरह का सामग्री समाज में वकीलों के प्रति नकारात्मक धारणा पैदा कर सकती है और पेशे की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है, संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वीडियो जानबूझकर इस तरह प्रस्तुत किया गया जिससे अधिवक्ताओं की छवि धूमिल हो और उनके कार्य पर सवाल उठाए जाएं।

आवश्यक बैठक में लिया गया सर्वसम्मति से निर्णय

मामले की गंभीरता को देखते हुए 04 फरवरी 2026 को जिला अधिवक्ता संघ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने वीडियो की सामग्री पर आपत्ति जताते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले को कानूनी रूप से उठाना जाएगा, बैठक में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी पेशे या समुदाय के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

वया है पूरा मामला ?

फेसबुक इंटरव्यू बना विवाद की वजह

अधिवक्ता संघ द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, रघुनाथ पोद्दार उर्फ कड़ू तथा 'दस्तक' नामक चैनल के संचालक शराफत अली के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि 25 जनवरी 2026 को शराफत अली ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से रघुनाथ पोद्दार का एक इंटरव्यू प्रसारित किया था, संघ का कहना है कि इस वीडियो इंटरव्यू में रघुनाथ पोद्दार ने वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत में उल्लेख है कि इंटरव्यू के दौरान वकीलों पर राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर नेक्सस चलाने तथा प्रोपेगेंड करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जिससे अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

पिकअप ने दो बाइकों को मारी टक्कर, एक युवक की मौत



-संवाददाता- सूरजपुर, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

कोतवाली थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर मार्ग स्थित सूतिया नाला के पास शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप के चालक ने नियंत्रण खो दिया और दोनों बाइकों को टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बैकुंठपुर मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा

सूतिया नाला हाईवे पर भीषण हादसा- तीन लोग गंभीर घायल, ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा

हादसे के बाद जुटी भीड़, चालक पुलिस के हवाले

दुर्घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और घायल व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया, स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई।

पुलिस जांच में जुटी, घायलों का उपचार जारी

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वाहन चालक से पूछताछ जारी है।

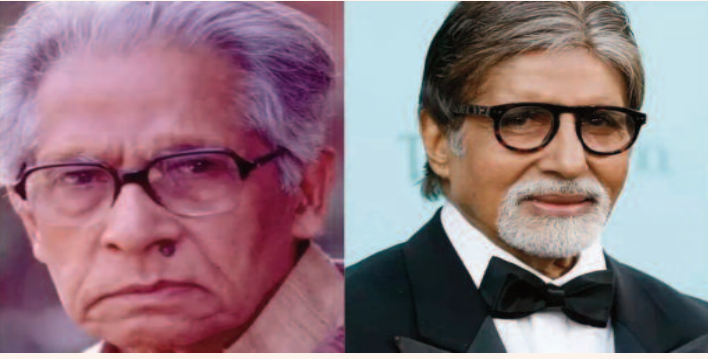
अवैध स्कैप यार्ड पर पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में वाहनों के पुर्जे जब्त

-संवाददाता- कोरबा, 07 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मागदर्शन में थाना उरगा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में थाना उरगा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरबसपुर बायपास रोड स्थित एक स्कैप यार्ड में अवैध रूप से भारी मात्रा में चोरी से संबंधित लोहे का सामान, हाइवा, ट्रेलर एवं ट्रक के पुर्जे संग्रहित कर रखे गए हैं। सूचना पर थाना उरगा पुलिस एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई। जांच के दौरान स्कैप यार्ड संचालक नूर आलम

पता माह. मुरजा, उम्र 33 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 23, टी.पी. नगर, कोरबा (छ.ग.) मौके पर उपस्थित मिला। यार्ड में रखे गए वाहनों के पुर्जे एवं लोहे के सामान के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहने पर उसके द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेजों के अभाव में उक्त सामग्री के अवैध होने की आशंका पर पुलिस द्वारा विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए मौके से भारी मात्रा में ट्रेलर की मंडी, डाला बाँड़ी एवं अन्य लोहे का सामान लगभग 1200 टन, अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये की गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। नगर निगम टीम द्वारा पंचनामा तैयार कर स्कैप यार्ड को सीलबंद किया गया। उक्त प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।

अमिताभ को कैसे मिला बच्चन सरनेम



विग बी के पिता ने किया था कुछ ऐसा

अमिताभ बच्चन आज इंडस्ट्री के महानायक हैं लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चन विग बी का असली सरनेम नहीं है। इस सरनेम के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हिंदी सिनेमा के मेगास्टार अमिताभ बच्चन सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं। 5 पांच दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव विग बी ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। बच्चन सुनते ही फैंस के दिमाग में सिर्फ उनका नाम आता है, हालांकि आपको बता दें कि यह उनका रियल सरनेम नहीं है और साथ ही वे परिवार में पहले थे जिनके नाम के पीछे सबसे पहले बच्चन लिखा गया था।

कैसे मिला विग बी को बच्चन सरनेम

बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने सरनेम के बारे में किस्से शेयर किए हैं और बताया है कि बच्चन उनके पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन का लिखने का नाम था। 76 साल के इस फिल्मी आइकन ने अपने बच्चा पर प्राचीन भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था के बारे में बात की थी। उन्होंने लिखा, इस देश में जाति व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, जिसका कई लोग पूरी लगन से पालन करते हैं और अब कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारे समाज को परेशान किया है, कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे।

पिता को पर्यटन नहीं थी जाति व्यवस्था

विग बी ने बताया कि उनके पिता जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने लिखा,

बाबूजी का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था और वह श्रीवास्तव थे। लेकिन उनका स्वभाव हमेशा जाति की बुराई के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम, अपना तखल्लुस, अपना पेन नेम बच्चन रखा। बड़े-बड़े कवि और लेखक अक्सर अपना नाम उपनाम से रखते थे। तो बच्चन मेरे पिता का पेन नेम, उनका काव्यात्मक उपनाम बन गया।

पहली बार विग बी ने अपनाया सरनेम
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तब और ज्यादा मान्यता मिली जब मेरा जन्म हुआ, जब मुझे पहले स्कूल में एडमिशन दिलाया गया और टीचरों ने पूछा कि इस लड़के का सरनेम एडमिशन फॉर्म में क्या भरा जाए, तो मेरी मां और पिता ने जल्दी से बात की और यह तय हुआ कि बच्चन ही परिवार का सरनेम होगा। एक्टर ने कहा कि वह बच्चन सरनेम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने लिखा, और यह ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा... मेरे पिता... बच्चन (और) मैं इस सरनेम को रखने वाला गर्वित व्यक्ति।

अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्मों दी हैं और उन्हें सिनेमा में योगदान के लिए पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। वहीं उन्हें सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे 83 की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव हैं।

नागिन मूवी में इस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहती थीं एकता कपूर, पर नहीं बनीं बात



एकता कपूर नागिन की लोककथा पर एक फिल्म बनाना चाहती थीं, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने एक अभिनेत्री को चुना था जो बाद में अमेरिका चली गईं। एकता का मानना है कि भारतीय दर्शक पश्चिमी सुपरहीरो फिल्मों को पसंद करते हैं, लेकिन अपनी लोककथाओं को नजरअंदाज करते हैं। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने हाल ही में खुलासा किया था कि वह टीवी सीरीज के बजाए नागिन की

लोककथा पर एक फिल्म बनाना चाहती थीं, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने एक अभिनेत्री को चुना था जो बाद में अमेरिका चली गईं। एकता का मानना है कि भारतीय दर्शक पश्चिमी सुपरहीरो फिल्मों को पसंद करते हैं, लेकिन अपनी लोककथाओं को नजरअंदाज करते हैं। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने हाल ही में खुलासा किया था कि वह टीवी सीरीज के बजाए नागिन की

फिल्म बनाना चाहती थीं। लेकिन उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया। **भारतीयों को सुपरहीरो में इंटरस्ट**
अब एकता ने फिल्म की कास्टिंग को लेकर हिट दिया है। एकता ने बताया कि उन्होंने इसके लिए एक्ट्रेस भी सेलेक्ट कर ली थीं। एकता ने बताया कि भारतीय दर्शक वेस्टर्न सुपरहीरो फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं, जबकि अक्सर वे अपने देश में बनी लोककथाओं पर आधारित कहानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। **अमेरिका चली गईं एक्ट्रेस**
फिल्ममेकर ने किस अभिनेत्री के नाम पर सहमति जताई थी उस पर भी बात की। एकता ने कहा कि पहले तो उस एक्ट्रेस ने हां कहा लेकिन वो अमेरिका चली

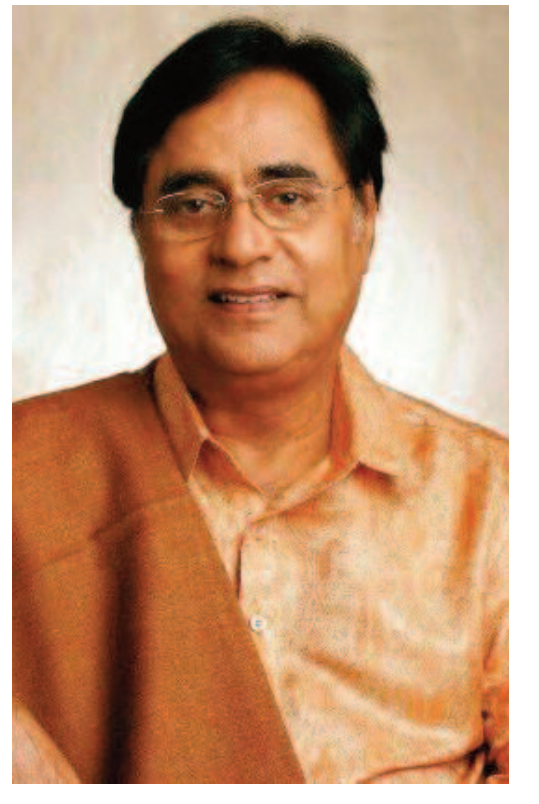
गईं। सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि उनका इशारा प्रियंका चोपड़ा की ओर था। **दादा-दादी से सुनते थे कहानियां**
उन्होंने उमा काकडे प्रोडक्शंस से बातचीत में कहा, भारत में पौराणिक कथाएं यहाँ के लोगों के दिलों में रची-बसी हैं। हम अपने दादा-दादी से ये कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं। भारत में हर बच्चा जानता है कि नागिन बदला लेती है। फिर भी, हम बैटमैन और सुपरमैन जैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन हम अपनी भारतीय लोककथाओं को अपने पढ़ें पर दिखाने के बारे में नहीं सोचते, फिर चाहे वो टेलीविजन हो या फिल्म। बता दें कि एकता कपूर का पॉपुलर शो नागिन कई पार्ट्स में टीवी पर आ चुका है। एकता ने नागिन सीरीज के कई सीजन प्रोड्यूस किए हैं, जो टेलीविजन पर काफी लोकप्रिय हुए। अभी इसका सातवां सीजन टीवी पर प्रसारित हो रहा है।

जब जगजीत सिंह की गजल सुनने के लिए पायलट ने रोक दी थी लैंडिंग

जगल किंग जगजीत सिंह की 8 फरवरी को 85वां बर्थ एनिवर्सरी है। अपनी मधुर आवाज से जगजीत सिंह ने सिर्फ इंडियन फैंस का ही नहीं, बल्कि विदेशी ऑडियंस का भी दिल जीता। उनका बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम आपको उनसे जुड़े एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं, जब पायलट ने आधे घंटे तक उनकी गजल की वजह से फ्लाइट रोक दी। जब-जब गजल की बात होती है, तब-तब दिमाग में बस एक ही नाम आता है, जो जगजीत सिंह का है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी गजलें गाई हैं, जो लोगों के दिलों में अभी भी बसी हुई हैं और श्रोता उनको यूट्यूब पर अभी भी सुनते हैं। जगजीत सिंह की 8 फरवरी को 85वां बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। गजल किंग की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां ऐसी हैं, जो सीधा दिलों को छूती हैं। इन्हीं में से एक किस्सा उनके पाकिस्तान

से इंडिया लौटने का है, जहाँ उनकी गजल के लिए पायलट ने विमान को रोक के रखा। **पायलट ने आधे घंटे दिल्ली में देर से पहुंचाई फ्लाइट**
जगजीत सिंह की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पड़ोसी मुल्क के लोग भी उनकी गजलों के दीवाने थे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गजल किंग जगजीत सिंह एक बार कराची से अपना एक शो खत्म करके फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे थे। जब वह फ्लाइट में बैठ रहे थे, तो कुछ लोगों को ये पता चला कि उनके बीच जगजीत सिंह हैं। बस फिर क्या था, उनमें से एक जगजीत सिंह की गजल से इतना प्रभावित था कि उसने सिंगर से कुछ गजलें सुनाने का अनुरोध किया। जगजीत सिंह ने भी प्लेन में मौजूद ऑडियंस का दिल नहीं तोड़ा और खुशी-खुशी उनकी ये गुजारिश पूरी कर दी। जब जगजीत सिंह ने अपने को-पैसेजर्स को गजल सुनाना शुरू किया, तब पायलट भी उनकी आवाज से इतना मंत्रमुग्ध हुआ कि उसने कंट्रोल रूम को यह इन्फॉर्म किया कि उनकी फ्लाइट को दिल्ली पहुंचने में आधे घंटे की देरी हो जाएगी।

फिल्मी गाना गाने के चकर में खाई थी मार
8 फरवरी 1941 में राजस्थान के गंगानगर में जन्में जगजीत सिंह का असली नाम जगमोहन सिंह था। उनका जन्म धर्मनिष्ठ सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सरदार अमर सिंह धमानी, भारत सरकार के कर्मचारी थे। दरअसल, जगजीत सिंह के पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बनें, लेकिन बचपन से ही उनका रुझान संगीत की तरफ था।



खेल-समाचार

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच की उम्मीद जगी

श्रीलंका क्रिकेट ने कहा... हमें रेवेन्यू में नुकसान होगा पीसीबी ने भरोसा दिलाया सरकार से बात करेंगे

नई दिल्ली, 07 फरवरी 2026। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उम्मीद जगी है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मैच पर दोबारा विचार करने की अपील की है। पीसीबी 15 फरवरी को होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के बहिष्कार के फैसले पर सरकार से बातचीत करेगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से कहा न कहां, हम भारत के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। अगर भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होता है तो हमें रेवेन्यू में भारी नुकसान होगा। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने एक फरवरी को पीसीबी को टूर्नामेंट में टीम भेजने की मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। भारत-पाक मैच आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे बड़ा कर्माग्निष्ट मुकाबला माना जाता है, ऐसे में अब इस पर दोबारा बातचीत की संभावना बन गई है।

श्रीलंका ने पीसीबी से कहा... इमेज को नुकसान होगा

इस मुद्दे को लेकर श्रीलंका क्रिकेट ने पीसीबी को मेल लिखा है। इसमें कहा गया है कि भारत-पाक मैच नहीं होने से श्रीलंका क्रिकेट को आर्थिक नुकसान होगा और टूर्नामेंट की इमेज को भी नुकसान होगा। श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के साथ मिलकर कर रहा है। **पाकिस्तान-श्रीलंका के रिश्ते अच्चे**
पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच सरकार और क्रिकेट स्तर पर हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, इसलिए पीसीबी इस अपील को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शमी सिल्वेला ने संपर्क किया। उन्होंने कहा... भारत-पाक मैच नहीं होने पर टिकट बिक्री और हॉस्पिटैलिटी से होने वाली अतिरिक्त कमाई भी खत्म हो जाएगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मोहसिन नकवी ने भरोसा दिलाया है कि वह इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगे। मीडिया में आई यह



खबर भी गलत बताई गई है कि पाकिस्तान की कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बायकोट करेगा। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद लिया। बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस्तामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड टी 20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। **आईसीसी बोला... पाकिस्तान अपने फैसले पर विचार करे**
आईसीसी ने एक फरवरी को ही देर रात 11 बजे मीडिया रिलीज में कहा, हम

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल कन्फ्रेंस में इंतजार कर रहे हैं। आईसीसी सरकार के फैसलों का समर्थन करता है, लेकिन पाकिस्तान का फैसला दुनियाभर में क्रिकेट के इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाला है। आईसीसी उम्मीद कर रहा है कि पीसीबी अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा ताकि दुनियाभर में क्रिकेट का सिस्टम प्रभावित न हो। पाकिस्तान खुद आईसीसी का सदस्य है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह सभी स्टेकहोल्डर्स को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला ले।

भारत तय समय पर श्रीलंका जाएगा
टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई सूत्रों ने साफ किया है कि भारतीय टीम तय कार्यक्रम के अनुसार ही श्रीलंका दौर पर जाएगी। टीम 15 फरवरी को श्रीलंका पहुंचेगी और आईसीसी के सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करेगी। हालांकि, मैच को लेकर अंतिम फैसला मैदान पर मौजूद मैच रेफरी द्वारा ही लिया जाएगा।

इलावेनिल ने गोल्ड जीता

शांभवी ने इतिहास रचकर टॉप पर जगह बनाई...
नई दिल्ली, 07 फरवरी 2026। ओलंपियन इलावेनिल वलारिवान ने 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट में जापान की मिसाकी नोबता को करीबी अंतर से हराकर गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। वहीं, शांभवी क्षीरसागर ने एशियन जूनियर फाइनल में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नई दिल्ली स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित चैंपियनशिप में मेघना सज्ज्वान ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पॉइंट्स पर जगह बनाई, जबकि मान्यता सिंह और अनंशा शर्मा के साथ मिलकर भारत को जूनियर महिला मेडल्स में क्लोन स्वीप हासिल करने में मदद की। भारत ने चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखते हुए प्रतियोगिता के चौथे दिन 10 गोल्ड मेडल जीते। इसी के साथ भारत के कुल मेडल्स की संख्या 43 हो गई है। इनमें 27 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज शामिल हैं। ओजस्वी टाकूर ने भी महिलाओं की यूथ कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत ने दिन की शुरुआत 50 मीटर पेंस पिस्टल इवेंट में पॉइंट्स पर दबदबा बनाकर की। पूर्व 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ल्ड नंबर 1 सोभर चौधरी ने गोल्ड पर निशाना साधा। उनके बाद कमलजीत चौधरी और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रविंदर सिंह ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। इनके अलावा, योगेश कुमार ने जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। इलावेनिल दो सीरीज के बाद पांचवें स्थान पर थीं, लेकिन 18वें शॉट तक पहुंचते-पहुंचते उन्होंने धीरे-धीरे बढ़त बना ली। उन्होंने धैर्य बनाए रखते हुए शीर्ष स्थान कायम रखा, जबकि नोबता मिसाकी और मेघना उनके काफी करीब रहीं। आर्या बोसे 9.8 का लो स्कोर लगाने के बाद पदक से चूक गईं, इसके बाद उन्होंने दो बार 10.2 लगाए। नोबता ने लगातार दो बार 10.8 के साथ फाइनल का समापन किया, जबकि इलावेनिल ने एलिमिनेशन चरण में औसतन 10.6 के साथ 10 सटीक हिट किए, जिनमें एक 10.9 भी शामिल था। भारतीय टीम ने संयुक्त रूप से 1892.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक भी जीता।

बीमारी के कारण जसप्रीत बुमराह पहला मैच नहीं खेल पाएंगे



मुंबई, 07 फरवरी 2026। बीसीसीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बीमारी के कारण यूएसए के खिलाफ भारत के 2026 टी 20 वर्ल्ड कप के पहले मैच के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी हालत पर करीब से नजर रख रही है। नतीजतन, मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, जिन्हें हाल ही में 15 खिलाड़ियों की टीम में बुमराह बीमारी के कारण यूएसए के खिलाफ भारत के पहले टी 20 वर्ल्ड कप मैच के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। जसप्रीत बुमराह बीमारी के कारण यूएसए

चार पूर्व विजेता फिर मैदान में

दुबई, 07 फरवरी 2026। रोजर फेडरर के रिकॉर्ड आठ टाइटल्स से लेकर नोबक जोकोविच के दबदबे तक-2009 से 2011 तक लगातार तीन जीत-दुबई इट्यूटी फी टेनिस चैंपियनशिप लंबे समय से पूर्व चैंपियंस के बीच एक लोकप्रिय इवेंट साबित हुई है। और यह परंपरा इस महीने भी जारी रहेगी क्योंकि पिछले चार पुरुष विजेता एक बार फिर मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। 23 से 28 फरवरी तक, दानिल मेदवेदेव, आंद्रे रुबलेव, ह्यूगो हम्बर्ट और स्टेफानोस पानोस सितसिपास सभी इसमें हिस्सा लेंगे, जो एलीट मुकाबले, रोमांचक कहानियों और उस खास स्लैमर का वादा करता है जिसने इस एटीपी 500 इवेंट को पुरुषों के कैलेंडर पर एक खास जगह दिखाई है। शहर के डब्ल्यूटीए 1000 टूर्नामेंट के एक हफ्ते बाद, जिसमें दुनिया की सभी टॉप 20 महिला खिलाड़ी शामिल थीं, अल-गरहूद में दुबई इट्यूटी फी टेनिस स्टेडियम एक बार फिर जगमगा उठेगा, जिसमें दुनिया के टॉप 20 पुरुष खिलाड़ियों में से आठ शामिल होंगे। इस साल 2023 के बाद यह पहली

बार है कि मेदवेदेव-जो दुनिया में नंबर 12 पर हैं - टूर्नामेंट के टॉप सीड नहीं हैं। उन्होंने 2023 में अपना एकमात्र दुबई खिताब जीता था, उस साल के टॉप सीड जोकोविच को सेमीफाइनल में हराकर। पूर्व विश्व नंबर 1, मेदवेदेव को अपनी पौढ़ी के सबसे प्रभावशाली हाई-कोर्ट खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिनमें मजबूत डिफेंसिव क्षमता और बेसलाइन से सटीक शॉट लगाने की काबिलियत है। सिल्वर दो ट्रॉफी उठाने के 18 महीनों के भीतर, मेदवेदेव विंबलडन में लगातार दो सेमीफाइनल और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। 2021 के यूएसए ओपन खिताब के साथ दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अभी भी उनसे दूर है, लेकिन इस साल उन्होंने ब्रिस्बेन में जीत के साथ एक मजबूत शुरुआत की है, जिससे उन्हें 22 वां एटीपी खिताब मिला है। मॉस्को के इस खिलाड़ी की दुबई वापसी को बड़ी संख्या में फैंस देखेंगे जो यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या यह लोकप्रिय 29 वर्षीय खिलाड़ी दुबई की रोशनी में एक बार फिर अपना दबदबा बना पाएगा।



देश की टॉप गोल्फर 14 वीं बीपीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में खेलेंगी

मुंबई, 07 फरवरी 2026। एक रिलीज के अनुसार, 14वीं बीपीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में देश भर की जानी-मानी गोल्फर हिस्सा लेंगी, जो 10 से 12 फरवरी तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब के शानदार मैदानों में खेले जाएंगी। यह इवेंट डब्ल्यूआईजीए द्वारा स्पॉन्सर और सीपीपी द्वारा को-स्पॉन्सर किया गया है, जिसमें पूरे भारत से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज डिवीजन में 96 एंटी

मिली हैं। बीपीजीसी लेडीज कैप्टन विजया सहजवाला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गोल्ड डिवीजन के खिलाड़ियों में बेंगलुरु की परीमिता मुखर्जी, जो एन्वहीटी टूर की टॉप रैंक वाली खिलाड़ी हैं, शामिल हैं, जबकि मुंबई की चुनौती का नेतृत्व उमा मेनन, सोनिया मल्होत्रा, मुग्धा दातार, भारती पुरकर और तन्वीम अली करेंगी। दिल्ली की खिलाड़ी सोनल चौधरी और डिंपल

सिंह से भी अच्छे प्रदर्शन को उम्मीद है। पिछले साल यह इवेंट बीपीजीसी की 18 साल की भूमिका भिसे ने जीता था, जो इस साल हिस्सा नहीं ले रही हैं, जिससे एक नए चैंपियन के लिए जगह खाली हो गई है। विजेता को शानदार महिंद्रा ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि सभी डिवीजन में सिल्वर पुरस्कार भी होंगे। सिल्वर डिवीजन में बेस्ट ग्रॉस स्कोर वाली गोल्फर को लेफ्टिनेंट कर्नल हरभजन सिंह ट्रॉफी दी जाएगी।

बस्तर पंडुम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ.....

छत्तीसगढ़ हमेशा घर जैसा लगता है, यहां की संस्कृति प्राचीन और सबसे मीठी : मुर्मू

जगदलपुर, 07 फरवरी 2026। राष्ट्रपति बोलें द्रौपदी मुर्मू ने कहा छत्तीसगढ़ आना हमेशा मुझे घर जैसा लगता है। यहां की संस्कृति प्राचीन और सबसे मीठी है। बस्तर पंडुम को लोग उत्सव की तरह जीते हैं। यहां की सुंदरता और संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। पिछले 4 दशक से नक्सलवाद के कारण बस्तर के आदिवासियों को नुकसान हुआ। लेकिन अब बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है। बड़ी संख्या में नक्सली हथियार डाल रहे हैं। मुर्मू ने आगे कहा, हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटें लोगों का स्वागत करती हूँ, जो लोग बरगला रहे हैं उनकी बातों में न आएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम में कही। इस दौरान सीएम ने उन्हें डोकरा आर्ट से बने कर्मा वृक्ष, कोसा शिल्प से तैयार गमछ भेंट किया।



डोकरा शिल्प ने बस्तर को विश्व पहचान दिलाई : राज्यपाल

इससे पहले राज्यपाल रमन डेका ने कहा, बस्तर पंडुम 2026 के शुभारंभ मौके पर यहां मौजूद होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ। हमारे पारंपरिक व्यंजन, कल्चर सभी मिलकर बस्तर की पहचान विश्व स्तर पर दिखाते हैं। यहां के लोग जल जंगल जमीन के बीच रहते हैं। गांव गांव से आए लोग अपनी कला और संस्कृति दिखा रहे हैं। मैं डोकरा कला का उल्लेख करना चाहूंगा, बस्तर की डोकरा कला देश विदेश में परसंद की जा रही है। यही हमारी पहचान है। यहां का जनजातीय और समाज हमें प्रकृति का संदेश देती है।

पंडुम केवल आयोजन नहीं, संस्कृति का मंच : सीएम साय

सीएम साय ने कहा कि बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और समृद्ध विरासत को समर्पित मंच है, जहां इस बार 12 विधाओं में 54 हजार से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल भय से पहचाने जाने वाले बस्तर में अब विकास का दौर है और 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर को नक्सलमुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहरा है। सीएम साय बोले- मां दत्तेश्वरी की पावन भूमि पर राष्ट्रपति का आगमन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बस्तर पंडुम का निमंत्रण स्वीकार कर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं प्रदेश की तीन करोड़ जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का बस्तर की माताओं-बहनों के प्रति विशेष अपनत्व है और यह संपूर्ण जनजातीय समाज के लिए गौरव का क्षण है।



सीएम साय ने राष्ट्रपति मुर्मू का जगदलपुर के मां दत्तेश्वरी एयरपोर्ट में आत्मीय स्वागत किया



देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में गरिमामय आगमन हुआ। वे यहां के ऐतिहासिक लावबाग मैदान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम का शुभारंभ करने पहुंची हैं। मां दत्तेश्वरी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आत्मीय स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री रोहन साहू और वन मंत्री केदार कश्यप ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। सांसद मंदेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव और महापौर संजय पांडे ने भी राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए स्वागत किया।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद पर लेंगे हाईलेवल मीटिंग... बस्तर पंडुम के समापन समारोह में होंगे शामिल

रायपुर, 07 फरवरी 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने दौरे के दौरान वे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के अनुसार, रायपुर के होटल मेफेयर में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें नक्सलवाद, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 8 फरवरी को अमित शाह रायपुर में आयोजित वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में नक्सल प्रभावित



क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, रणनीति और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। इसी दिन वे 'छत्तीसगढ़ @ 25 : शिफ्टिंग द लेंस' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्लेक्ट कर्मक्रम में भी भाग लेंगे। इसके बाद 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर जाएंगे। बस्तर में आयोजित बस्तर पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम का समापन करेंगे। अमित शाह के इस दौरे को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुकमा के बाद बीजापुर में बड़ा सरेंडर... 30 माओवादियों ने डाले हथियार, सिर पर था 85 लाख रुपए का इनाम

बीजापुर, 07 फरवरी 2026। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर बस्तर में एक के बाद एक जिले में माओवादियों का समर्पण जारी है। सुकमा में 21 माओवादियों के बाद बीजापुर में 30 माओवादियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है। इन 30 माओवादियों के सिर पर करीब 85 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरकार की महत्वपूर्ण 'नियद नेल्लानार' व पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक डिवीसीएम सहित कुल 30 माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 20 महिला माओवादी व 10 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इन 30 माओवादियों पर कुलमिलाकर 85 लाख का इनाम घोषित किया था। ये सभी आत्मसमर्पण माओवादी फायरिंग, आईडी ब्लास्ट और आगजनी जैसे अन्य घटनाओं में शामिल थे। माओवादियों ने सीआरपीएफ



डीआईजी देवेन्द्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.एन. यादव, डीएसपी शरद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को अधिकारियों ने 50-50 हजार रुपए नगद राशि प्रदान की गई। बता दें कि वर्ष 2024 से लेकर अब तक कुल 918 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, वहीं वर्ष 2025 से लेकर अब तक कुल 1163 माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा सुरक्षाबल के जवानों ने 231 माओवादियों को अलग-अलग मुठभेड़ में मार गिराया है। इन घटनाओं में शामिल रहे : ये सभी नक्सली सुरक्षा बलों पर हमलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसक वारदात, सड़क और निर्माण कार्यों में बाधा, हथियार और विस्फोटक

परिवहन, संगठन विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों जैसी गंभीर नक्सली घटनाओं में सलिस रहे हैं।

निर्णायक बदलाव हो रहा : एसपी

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने कहा कि, 21 माओवादी कैदों का हथियारों सहित आत्मसमर्पण यह दर्शाता है कि सुकमा जिले में शांति और विकास की दिशा में निर्णायक बदलाव हो रहा है। जिला पुलिस पुनर्वास और सम्मानजनक भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

माओवादी संगठन की जड़ें कमजोर

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि पूना मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान बस्तर में माओवादी संगठन की जड़ों को कमजोर कर रहा है। शेष कैदों से अपील है कि वे हिंसा छोड़ मुख्यधारा में लौटें।

ट्रांसफार्मर और कॉपर चोर गिरोह का मंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार



जांजगीर-चांपा, 07 फरवरी 2026। जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रांसफार्मर, कॉपर एवं एल्युमिनियम के बल चोरी करने वाले संगठित अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के माल के परिवहन के लिए बोलेरो वाहन को एम्बुलेंस का रूप देकर पुलिस व आम जनता को भ्रमित करते थे। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की गई सामग्री व वाहन बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 17,30,000 आंकी गई है। थाना शिवरीनारायण क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मरों से लगातार हो रही कॉपर चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। 13-14 जनवरी 2026 को रोड दुर्घटा के पास स्थित पुराने ट्रांसफार्मर से लगभग 230 किलो कॉपर चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद 22 जनवरी 2026 को लोहर्सी क्षेत्र से लगभग 200 किलो कॉपर वायर चोरी की शिकायत सामने आई।

फर्जी आदेश के दम पर वर्षों तक सरकारी नौकरी कर रहे चार कर्मचारी हुए बर्खास्त

खैरागढ़, 07 फरवरी 2026। राज्य शिक्षा आयोग के फर्जी आदेश के सहारे वर्षों तक सरकारी सेवा करने वाले चार कर्मचारियों को जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ अब उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आचार्यिक मामला दर्ज कराया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला वर्ष 2021 का बताया जा रहा है, जब टीकमचंद साहू, फगेंद्र सिंह, रजिया अहमद और अजहर अहमद को जिले के अलग-अलग स्कूलों में सहायक ग्रेड-3 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गई थी। इसके साथ ही डोलामणी मटारी, सादाब उस्मान, आशुतोष कछवाहा और अमीन शेख भी मोहला-मानपुर जिले के विद्यालयों में पदस्थ थे। नियुक्ति के दस्तावेजों की पड़ताल में चौकाने वाले तथ्य सामने आए।

रायपुर में टार-फैक्ट्री में भीषण आग... 5 घंटे बाद बुझी 22 किलोमीटर दूर से दिखा धुआं, ऑयल-केमिकल से फैली, मशकत के बाद पाया काबू



रायपुर, 07 फरवरी 2026। राजधानी रायपुर के भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित टार प्रोडक्शन फैक्ट्री में शनिवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। 5 घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग इतनी भीषण थी कि 22 किलोमीटर दूर से धुआं का गुब्बारा उठता दिखा।

होता है, यहां बड़ी मात्रा में ऑयल-केमिकल का इस्तेमाल होता था जिससे आग फैली थी। पानी का शॉटिंग होने के कारण भड़की आग : बताया जा रहा है घटना के बाद 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी। 3 घंटे तक पानी की 4 टंकी खाली हो चुकी थी। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इलाके में पानी का शॉटिंग हुआ जिससे दूर के स्टेशन से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही थी। इसी बीच आग भड़क गई।

अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल... तो सांसद बृजमोहन ने दिया करारा जवाब, कहा- छत्तीसगढ़ भाजपा का गढ़...

रायपुर, 07 फरवरी 2026। नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियानों की समीक्षा करने के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौर पर हैं। शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिसे लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। सांसद बृजमोहन ने कहा कि वे बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी के नेता आएं ही। छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा। आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद की दो सबसे बड़ी समस्या है, उन्होंने देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का ठाना है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए यहां आते हैं। कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विकास में कोई बाधा थी तो वह नक्सलवाद थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचीं। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रपति के आने से हमारा गौरव बढ़ता है। हम सब का सीमा है देश की राष्ट्रपति बस्तर पंडुम के उद्घाटन में पहुंचीं। हम सब उनका अभिवादन स्वागत करते हैं।

मनेन्द्रगढ़, 07 फरवरी 2026। सोशल मीडिया पर वकीलों के विरुद्ध कथित तौर पर की गई अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर जिला अधिवक्ता संघ मनेन्द्रगढ़ ने कड़ा ऐतराज जताया है। अधिवक्ता संघ ने इस मामले में सिटी कोतवाली प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता संघ द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, रघुनाथ पोद्दार उर्फ कल्लू और एक निजी चैनल के संचालक शराफत अली के खिलाफ यह तहरीर दी गई है। आरोप है कि 25 जनवरी 2026

को शराफत अली ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से रघुनाथ पोद्दार का एक वीडियो इंटरव्यू प्रसारित किया था। इस इंटरव्यू में रघुनाथ पोद्दार ने वकीलों के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित, अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वीडियो इंटरव्यू के दौरान रघुनाथ पोद्दार ने वकील समुदाय पर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर 'नक्सल' चलाने और प्रोपेगंडा फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ता संघ का कहना है कि इस प्रकार के बयान न केवल निराधार हैं, बल्कि इससे पूरे

मैनपुर-ओडिसा बॉर्डर में नक्सलियों का डंप किया हथियार बरामद...

गरियाबंद, 07 फरवरी 2026। मैनपुर-ओडिसा बॉर्डर में नक्सलियों का डंप हथियार बरामद किया गया है। जनवरी-2026 को गरियाबंद में आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में वापस लौटे माओवादियों से गहन पूछताछ करने के पश्चात् संगठन सीपीआई माओवादी के ओडिसा राज्य कमिटी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिला गरियाबंद के ओडिसा राज्य से लगे पहाड़ी श्रृंखलाओं में विभिन्न स्थानों पर आटोमेटिक हथियार एवं टैक्निकल टीम के वेपन वर्कशॉप के उपकरण सहित भारी मात्रा में अन्य सामग्रियों को डम्प कर रखे जाने की जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के आधार पर डम्प के स्थानों को चिन्हित कर

वकीलों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर मड़का जिला अधिवक्ता संघ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में की शिकायत...

वकील समुदाय की छवि को ठेस पहुंची है। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिया गया कड़ा निर्णय : मामले की गंभीरता को देखते हुए 04 फरवरी 2026 को जिला अधिवक्ता संघ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के भ्रामक और अपमानजनक वीडियो प्रसारित कर अधिवक्ताओं के प्रति समाज में अनादर की भावना पैदा की जा रही है। संघ के अनुसार करीब 13 मिनट के इस वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा।

